स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–18, अंक–12, मार्गशीर्ष–पौष 2067, दिसम्बर 2010

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011-26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 से मुद्रित।

आवरण कथा-0

पर्यावरण मंत्री जयराम रामेश ने जब कानकुन में चल रहे जलवायु सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान यह कहा कि भारत किसी भी लिखित समझौते को मानने पर विचार कर सकता है. . .

कवर पेज

अ नु क्र म

आवरण लेख
विकसित देशों की प्रभुताई, भारत की जग हसाई
– **विक्रम उपाध्याय** /5

भ्रष्टाचार
देश को भ्रष्टाचार की ओर धकेलती संप्रग सरकार
– **बलवीर पुंज** /8

मुद्दा
जीन संवर्धित फसलें एवं पर्यावरण
– **डॉ. सदाचारी तोमर** /12

वैश्वीकरण
विश्व बाजार की चुनौतियां
– **निरंकार सिंह** /14

आतंकवाद
नहीं लिया गया आतंकी हमले से सबक
– **जगमोहन** /17

जनता का फैसला
एक बार फिर विकास की ओर बिहार
– **अवधेश कुमार** /21

पर्यावरण
राष्ट्रीय नदी गंगा को बचाने के उपाय
– **राजेन्द्र सिंह** /25

अर्थ–तंत्र
प्राकृतिक संसाधनों को न्यायपूर्ण वितरण कीजिए
– **डॉ. भरत झुनझुनवाला** /28

कृषि
बर्बादी के बीजों को रोकिए
– **देविंदर शर्मा** /31

परिसंवाद
आजादी से आज तक किसी भी सरकार . . . /34

पाठकनामा /2, **आंदोलन** /13

पाठकनामा

शुद्ध दूध आए कहां से?

स्वदेशी पत्रिका में 'पशुधन' पर आधारित कई लेख पढ़ चुका हूँ। हमारे देश में गायों का क्या हाल है, सभी जानते हैं। दीपावली के समय मिट्ठाइयों अनेक प्रकार की मिलावट के बारे में चैनलों ने खूब दिखाया। अब तो यह भी डर लगता है कि कहीं हमारी चाय की चुस्की भी सिंथेटिक दूध की न हो। पत्रिका में लेख से ज्ञात होता है कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ हमने पशुधन के विकास का कोई लक्ष्य नहीं रखा इसलिए यह सवाल तो उठता ही है कि आखिर शुद्ध दूध आए कहां से...? दिल्ली में नगर निगम ने पशु पालने पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली से जुड़े एनसीआर में भी तेजी से शहरीकरण होने के कारण दुधारु पशु पालने लोगों ने ऐसे ही बंद कर दिए है। इसलिए ताजे दूध की बात ही बेकार है। सिर्फ कुछ कंपनियों पर पूरी जनसंख्या को दूध पिलाने का भार है। ऐसे में उन मिलावटखोरों की चांदी हो जाती है जो कम कीमत के नाम पर जहर पिलाते हैं। जब से भारत ने यूरोप आदि देशों को बीफ निर्यात करना शुरू किया है तब से दुधारु जानवरों की अकाल ही पड़ गई है। अब तो कई गैंग ऐसे हैं जो शहर से सटे इलाके से जानवरों को चुराकर सीधे कसाई घर में बेच देते हैं।

अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने गाय चोरों को पकड़ा जो एनसीआरं से गाय को चुरा कर उनका मांस बेचने का धंधा करते है। कहने को गोकशी पर रोक लगी है पर यह प्रभावी कहां है। ऐसे में शुद्ध दूध और पौष्टिकता की बात करना ही बेकार है।

राकेश कुमार दास, मीडिया अपार्टमेंट, गाजियाबाद

समाज और सरकार के संयुक्त प्रयास से होगा – गरीबी उन्मूलन

भारत को स्वतंत्र हुए 63 वर्ष हो गए, इस बीच दुनिया में भारत का नाम तेजी से उभरा। आज अमेरिका, चीन, जापान जैसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत राष्ट्रों के साथ हम भी कंधा से कंधा मिला रहे हैं, पर जिस तरह भ्रष्टाचार और महंगाई हमारे समाज में घर करती जा रही है, उससे तो नहीं लगता कि हम ज्यादा दिन तक इस बोझ को बर्दास्त कर पाएंगे। आर्थिक सुपर पावर बनने के लिए भारत को बेरोगारी और गरीबी आदि दुष्कारकों पर अंकुश लगाना होगा। अभी भी हमारे यहां भूखमरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 21 करोड़ लोगों को कम से कम एक शाम भूखा रहना पड़ता है। मनरेगा लोगों की हालत बदलने में सफल नहीं हो पाई है। हजारों लोग आत्महत्या कर रहे हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है पर परिणाम सकारात्मक नहीं आ रहे हैं। सरकार और समाज के संयुक्त प्रयास से ही इस समस्या का समाधान होगा। सभी को काम और काम के बदले उचित दाम मिलें, तभी भारत विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंचेगा।

– राजेन्द्र सिंह ठाकुर जिला प्रमुख, ग्राम भारती, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com
अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क ***'स्वदेशी पत्रिका'*** दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

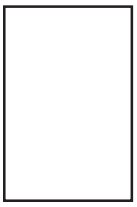

मैं चाहती हूं कि दुनिया यह जाने कि करकरे को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मारा न कि किसी कथित हिंदू कट्टरवादी संगठन ने।

– कतिवा करकरे
(शहीद हेमंत करकरे की विधवा)

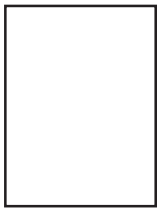

करकरे ने शहीद होने से दो घंटे पहले मुझे फोन कर कहा था कि हिंदू चरमपंथियों से उनकी जान को खतरा है।

दिग्विजय सिंह, कांग्रेस महासचिव–

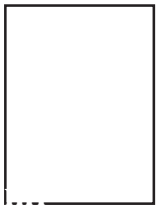

दिग्वियज सिंह के बयान से देश की सुरक्षा, आंतकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई और 26/11 की जांच को गहरा धक्का पहुंचा है, पाकिस्तान उनके बयान का फायदा उठाएगा।

– रविशंकर प्रसाद,
भाजपा प्रवक्ता

आकंठ भ्रष्टाचार और जड़ सरकार

कई घोटालों में फंसी सरकार देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह भागती नजर आ रही है। लाखों–करोड़ों रुपये के घोटाले सामने आने के बाद होना यह चाहिए था कि सरकार संसद में ऐलान करती कि वह हर तरह की जांच के लिये तैयार है, चाहे वह संयुक्त संसदीय दल से जांच कराने का मामला ही क्यों न हो? लेकिन सरकार राजनीतिक मंच पर इस मामले को लाना नहीं चाहती। जाहिर है सरकार मामले की लीपा–पोती में लगी है। घोटाले के इस झमेले में एक नया मोड़ यह आ गया है कि अब खुलेआम निजी कंपनियां भी राजनीतिक दलों का पक्ष लेने लगी हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं मंत्री, अधिकारी और कोरपोरेट जगत मिलीभगत कर देश को लूटने में लगे हैं।

यह तथ्य पहले भी सामने आया है कि किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिये सरकारी नीतियां तक बदल दी गयी हैं। रिलायंस, टाटा, सत्यम आदि अनेक ऐसे नाम हैं जिनके साथ राजनीतिक गठजोड़ और धोखाधड़ी की कहानियां खुलती जा रही हैं।

उदारीकरण का एक विद्रूप चेहरा यह भी है। पूंजीवाद के पोशक सत्तातंत्र में जनतंत्र को बांदी बनाकर छोड़ दिया है जिसको जिस तरह चाहे मोड़ा जा सकता है, निभाया जा सकता है और भ्रष्ट किया जा सकता है। हालांकि भ्रष्टाचार अकेले भारत का मामला नहीं है। पूरी दुनिया में इस समय भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पर भारत जरा इसमें भी आगे बढ़कर है।

अभी हाल ही में एक खबर है कि भारत का हर दूसरा व्यक्ति रिश्वत देता व लेता है। रिश्वत को हमने शाश्वत मान लिया है। रिश्वत न सिर्फ काले धन का स्रोत है बल्कि रिश्वत के कारण उन लोगों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता जिनके पास पूंजी कम है और मेहनत के बलबूते कुछ आगे करना चाहते हैं। जो समाज को स्वच्छ रखने का दंभ भरते हैं और जो व्यक्ति के चरित्र को स्थायी पूंजी मानते हैं। ऐसे लोगों की भी इच्छा शक्ति ढोलने लगी है।

पिछले कुछ वर्षों में यह आम देखने को मिला है कि जिसने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठायी है और जिसने भी व्यवस्था की पोल खोलने की कोशिश की है उसका हश्र बहुत बुरा हुआ है या तो उसे जान से मार दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है या फिर उसे खिला–पिलाकर भ्रष्टाचार की नदी में डूबो दिया गया है। यह जिम्मेदारी समाज व सरकार दोनों की है कि भ्रष्टाचार के इस रूप को जड़ से खत्म करें लेकिन सरकार के रवैये से तो नहीं लगता कि भ्रष्टाचार के प्रति लड़ाई लड़ने में मनमोहन सिंह जरा भी इच्छुक हैं। कुछ इस्तीफे, कुछ फेरबदल और कुछ नाम के लिये कार्यवाही सरकार इसी को भ्रष्टाचार की लड़ाई की इतिश्री मानती है। पता नहीं यह देश किधर जायेगा, लोग कब तक सुशासन की आस लगाये बैठे रहेंगे।

With Best Compliments from :

BHALOTIA MOTORS

(Authorised Mahindra Dealer)

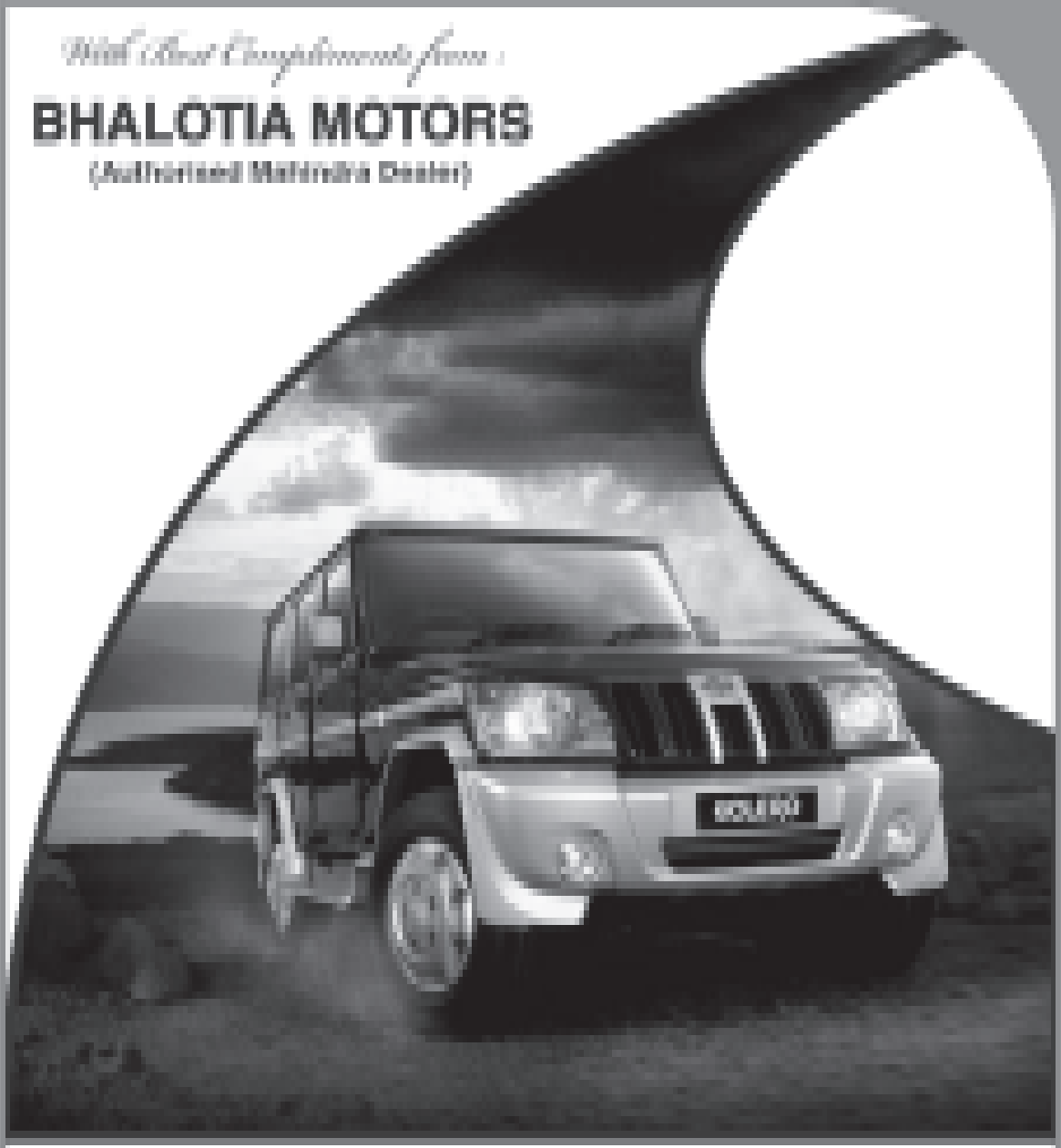

BHALOTIA MOTORS

(Sales & Service)

7th Phase, Industrial Area
Adityapur- Gamharia Main Road, Jamshedpur
Phone : 0657-2407497, 2408889
Mob. : 9234457153, 9234457154, 9234457157
E-Mail : bhl@mahindramail.com / bhalotiajsr@rediffmail.com

कानकुन में पर्यावरण सम्मेलन

विकसित देशों की प्रभुताई, भारत की जग हसाई

पर्यावरण मंत्री जयराम रामेश ने जब कानकुन में चल रहे जलवायु सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान यह कहा कि भारत किसी भी लिखित समझौते को मानने पर विचार कर सकता है तो जी 20 के देशों समेत तमाम उन संगठनों की आंखे आश्चर्य से फटी रह गई जो यह चाहते हैं कि अमरीका समेत दुनिया के वे देश जलवायु को बचाने के लिए अपनी वचनबद्धता दुहराये और पर्यावरण के अनुकूल अपने यहां के उद्योगों को चलाने का कानून बनाए. . .

कानकुन में अवसर था कि धरती को बचाने के लिए सभी देश एक ठोस पहल करते। कम से कम वे देश अपनी वचनबद्धता जरूर दोहराते, जिनकी आर्थिक उन्नति की होड़ ने पूरी दुनिया के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन यह सम्मेलन इस बात के साथ खत्म हो गया कि आगे भी सम्मेलन होता रहेगा।

■ **विक्रम उपाध्याय**

पर्यावरण मंत्री जयराम रामेश ने जब कानकुन में चल रहे जलवायु सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान यह कहा कि भारत किसी भी लिखित समझौते को मानने पर विचार कर सकता है तो जी 20 के देशों समेत तमाम उन संगठनों की आंखे आश्चर्य से फटी रह गई जो यह चाहते हैं कि अमरीका समेत दुनिया के वे देश जलवायु को बचाने के लिए अपनी वचनबद्धता दुहराये और पर्यावरण के अनुकूल अपने यहां के उद्योगों को चलाने का कानून बनाए साथ ही अभी तक जो पर्यावरण का नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए विकासशील देशों को आर्थिक मदद दे। पर यह क्या विकसित देशों से कुछ भी स्वीकार कराए बिना भारत एक तरह से अमरीका की उस मांग पर अपनी सहमति का आश्वासन दे दिया जिसमें कहा जा रहा है नए पनप रहे औद्योगिक देश अपने विकास की कीमत पर पर्यावरण को बचाने के लिए उनके द्वारा तय किए गए उत्सर्जन के मापदंड को मान ले, जबकि अति औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरण के लिए खतरा अमरीका और यूरोप आदि के देशों ने पैदा कर दिया है।

विकसित देशों ने अपनी ओर से बस इतना मौखिक आश्वासन दिया है कि वर्ष 2020 तक वे अपने यहां औद्योगिक उत्सर्जन 25 से 40 फीसदी कम कर देंगे, बदले में वे चाहते हैं कि दुनिया के बाकी विकासशील देश एक ऐसे मसौदे पर हस्ताक्षर कर दें जिसमें यह शर्त रखी जाए कि अगले दस वर्षों में विकासशील देश अपने औद्योगिक उत्सर्जन का स्तर 1990 के स्तर तक ले आए। इसका अर्थ यह है कि भारत समेत दुनिया के तमाम विकासशील देश उस उदारीकरण पूर्व काल में पहुंच जाएं जहां कुछ गिने–चुने विकसित देश औद्योगिक उत्पादन करें और बाकी देश उनके यहां से सिर्फ आयात करें। जो पर्यावरण बिगाड़ने के दोषी हैं वे ही पर्यावरण को बचाने के नए मापदंड बनाए और खुद उससे अपने आपको अलग कर लें।

यह तो अच्छा रहा कि कानकुन में कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ और बस इस बात की सहमति बनी कि तप रही धरती को बचाने के लिए आगे भी बातचीत जारी रहे। इस कानकुन सम्मेलन की समाप्ति के बाद अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा मैक्सिको की सरकार को बधाई दी कि उसने सभी देशों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि 2011 के डरबन सम्मेलन में ये सभी पक्ष इसी तरह बातचीत जारी रखेंगे। दरअसल जलवायु के मुद्दे भी उसी तरह पेचीदे हैं जिस तरह

विश्व व्यापार संगठन के मुद्दे। दोनों ही स्थितियों में अमरीका और यूरोप के विकसित देशों अपने हितों से समझौता किए बिना चाहते हैं कि विकासशील देश ही सभी तरह के त्याग करें और इसके लिए वे इन विकासशील देशों पर दबाव बनाते हैं और कुछ अहसानों को बदलें सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार कर लेते हैं।

जैसे ही कानकुन से यह खबर आई कि भारत ने अपनी पूर्व स्थिति से हटने की इच्छा सार्वजनिक कर दी है, अमरीका के दबाव में यह स्वीकार कर लिया है कि पर्यावरण के मामले में भारत किसी भी लिखित अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, यहां राजनीतिक गलियारों में बड़ी तेज प्रतिक्रिया हुई।

भाजपा ने कहा कि यह संसद द्वारा पास प्रस्ताव के बिल्कुल उलट है, तो वामपंथियों ने कहा कि यह देश हित के साथ सौदा है। पर कांग्रेस ने इस मामले पर देश को विश्वास में लेने के बजाए अहंकारी रवैया अपनाया उसके प्रवक्ता मनीष तिवारी ने विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा – उन्हें यह भी मालूम है कि कानकुन कहा हैं। अलबत्ता प्रधानमंत्री ने बाद में यह जरूर कहा कि कानकुन में हमने अपने पूर्व के स्टैंड को कायम रखा है। लेकिन सम्मेलन में गये पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने अपनी दूसरी मजबूरी बताई। उन्होंने यह दलील दी कि चूंकि बातचीत जारी रहे इसलिए भारत अपनी ओर से कुछ सकारात्मक पहल कर रहा है।

पहल तो उन 40 विकसित देशों को करनी है, जिन्होंने क्योटो में इस बात की सहमति जताई थी कि वे समयबद्ध चरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि विकासशील देशों को वैकल्पिक ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए वे आर्थिक मदद भी प्रदान करेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा तंत्र नहीं बना है, जिसके जरिए इन विकसित देशों को उनके दायित्व के बारे में बताया जा सके या दायित्व पूरा करने के लिए दबाव बनाया जा सके। इसके उलट चीन की उत्पादन क्षमता से डरकर अमरीका आदि देश इस प्रयास में लगे हैं कि किस तरह उनका औद्योगिक उत्पादन बढ़े, इसके लिए वे किसी भी उद्योग और कोई भी उर्जा स्रोत के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। वे इस मामले में किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते से बंधने के लिए तैयार नहीं। कारण वे अपनी आर्थिक और औद्योगिक प्रभुत्ता को किसी भी कीमत पर कम करने के लिए तैयार नहीं। यह जानना आवश्यक है कि पूरे विश्व में कुल तीन ही ऐसी महाशक्ति हैं, जो कुल कार्बन उत्सर्जन का 60 फीसदी हिस्सा अकेले उत्सर्जित करती हैं।

इस तालिका में सबसे ऊपर चीन है, जो पूरे विश्व के कार्बन उत्सर्जन का अकेले 22.30 फीसदी कार्बन कचरे को पर्यावरण में भेजता है। उसके बाद अमरीका ही है, जिसका प्रतिशत लगभग 20 है। तीसरे नंबर पर यूरोपीय यूनियन, जिसमें लगभग 27 देश शामिल हैं, ये देश कुल कार्बन उत्सर्जन का 14 फीसदी कार्बन पर्यावरण में छोड़ता है।

विकासशील देशों में भारत सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश है, जो लगभग पांच फीसदी कार्बन कचरा पर्यावरण में छोड़ता है।

कानकुन में अवसर था कि धरती को बचाने के लिए सभी देश एक ठोस पहल करते। कम–से–कम वे देश अपनी वचनबद्धता जरूर दोहराते, जिनकी आर्थिक उन्नति की होड़ ने पूरी दुनिया के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन यह सम्मेलन इस बात के साथ खत्म हो गया कि आगे भी सम्मेलन होता रहेगा। बातचीत इस पर खत्म हुई कि आगे भी बातचीत जारी रहेगी। कानकुन से विदा डरबन में मिलेंगे।

हां इस कड़वी बैठक में एक चीज चासनी के साथ जरूर सामने आई कि विकसित देशों के पैसे से एक ऐसा कोष जरूर बनेगा, जिसका उपयोग विकासशील देशों को वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत मुहैया कराने के लिए किया जाएगा। यानी विकसित देश पर्यावरण को प्रदूषित करते रहेंगे और विकासशील देश अपने त्याग से उसकी भरपाई करेंगे।

सवाल यह उठता है कि यदि यूं ही अपने–अपने पक्ष पर विकसित देश अड़े रहेंगे तो क्या दुनिया 2040 तक ऐसे ही बची रहेगी, जहां यह लक्ष्य रखा गया है कि तब तक पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई कर ली जाएगी और कार्बन उत्सर्जन की सीमा वहां लाई जाएगी जहां प्रकृति या पर्यावरण की सहन सीमा है। ❑

CTM
Suitings & Shirtings
Chawla Textile Industries Pvt. Ltd.
B-60, Industrial Area, Ludhiana
Phone: 0161-5054544, 4626586
9876302073, 98763-01817
Leading Indian Brand in
Textile Fashion

RAMKRISHNA
Forgings Limited

Plant-II & IV, Plot No. M-12, 16 & NO-26, Phase-VI, Industrial Area, Adityapur,
Jamshedpur-832 108, Jharkhand (India)
Ph.: 0657-2204249, Fax: 0657-2202914, E-mail: cso-division@ramkrishnaforgings.com

TUV NORD
ISO/TS 16949

Regd. & Corporate Office

L&T Chambers, 6th Floor, 16, CAMAC Street, Kolkata - 700 017
West Bengal (India), Phone: (+91 33) 3984 0999, Fax: (+91 33) 3984 0998
E-mail : info@ramkrishnaforgings.com

Works

Plant-I, Plot No. M-6, Phase-VI, Gamharia, Jamshedpur - 832 108, Jharkhand
Phone: (+91 657) 3204242, 3204249, Fax: (+91 657) 2202914,
Email: forgings-division@ramkrishnaforgings.com

Plant-II, 7/40, Duffer Street, Liluah, Howrah - 711204, W.B.
Phone: (+91 33)2654 3365, Fax: (+91 33) 2654 5729

Website: www.ramkrishnaforgings.com

देश को भ्रष्टाचार की ओर धकेलती संप्रग सरकार

घोटालों और भ्रष्टाचार के नित सामने आते मामले संप्रग सरकार की पूरे साल की कमाई कही जा सकती है। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर भले ही स्वच्छ छवि के हों, किंतु 2–जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के रुख से साफ है कि पारदर्शिता और शुचिता के मामले में सत्ताशिखर पर भी मलीनता कायम है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट के अनुसार स्पेक्ट्रम आवंटन में प्रावधानों की अनदेखी किए जाने के कारण राजकोष को करोड़ों रुपये का चूना लगा है।

कांग्रेस साफ–सुथरी सरकार चलाने का दावा करती है, किंतु संप्रग सरकार की पहली और दूसरी पारी में हुए एक के बाद एक घोटाले कांग्रेस के थोथे दावों की कलई खोलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में मची लूट और मुंबई का आदर्श सोसायटी घपला कांग्रेस की भ्रष्ट कार्यशैली को ही उजागर करता है। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन पर जितनी लागत का प्रारंभिक बजट बनाया गया था, खर्च उससे 15 से 20 गुना ज्यादा किया गया।

■ **बलबीर पुंज**

घोटालों और भ्रष्टाचार के नित सामने आते मामले संप्रग सरकार की पूरे साल की कमाई कही जा सकती है। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर भले ही स्वच्छ छवि के हों, किंतु 2–जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के रुख से साफ है कि पारदर्शिता और शुचिता के मामले में सत्ताशिखर पर भी मलीनता कायम है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट के अनुसार स्पेक्ट्रम आवंटन में प्रावधानों की अनदेखी किए जाने के कारण राजकोष को करोड़ों रुपये का चूना लगा है। कैग ने कहा है कि यदि 3–जी स्पेक्ट्रम के लिए अपनाई गई दरें 2–जी के मामले में अपनाई गई होतीं तो सरकार को एक लाख 76 हजार करोड़ रुपयों की अतिरिक्त प्राप्ति होती।

रिपोर्ट के अनुसार 122 में से 85 लाइसेंस अयोग्य कंपनियों को दिए गए। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अचल संपत्तियों का कारोबार करने वाली कंपनियों को अनुचित तरीके से लाइसेंस दिए गए। यूनिटेक बिल्डर्स एंड इस्टेट, हडसन प्रापर्टीज, अजारे प्रोपर्टीज और वोल्गा प्रोपर्टीज समेत नौ ऐसी कंपनियां हैं जिनका दूरसंचार कारोबार से कोई लेना–देना नहीं था।

लंबे समय से विपक्ष की आपत्ति के बावजूद जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दूरसंचार मंत्री ए राजा के संरक्षण में खड़े रहे तो राजा हर बार अपने बचाव में यही कहते रहे कि आवंटन प्रक्रिया की पग–पग की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाती रही है।

2008 में ही जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर राजा के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति मांगी थी। दो सालों तक प्रधानमंत्री द्वारा इस पर कोई सुनवाई नहीं होने पर स्वामी ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई। अब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री से उनकी चुप्पी का कारण पूछा है।

भ्रष्टाचार की सड़ांध आने तक प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या केवल गठबंधन की मजबूरी थी?

कांग्रेस साफ–सुथरी सरकार चलाने का दावा करती है, किंतु संप्रग सरकार की पहली और दूसरी पारी में हुए एक के बाद एक घोटाले कांग्रेस के थोथे दावों की कलई खोलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में मची लूट और मुंबई का आदर्श सोसायटी घपला कांग्रेस की भ्रष्ट कार्यशैली को ही उजागर करता है। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन पर जितनी लागत का प्रारंभिक बजट बनाया गया था, खर्च उससे 15 से 20 गुना ज्यादा किया गया। एक अनुमान के अनुसार खेलों पर 87 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। खेलों के लिए 2005–06 का केंद्रीय बजट 45.50 करोड़ रुपये था, जो 2009–10 में बढ़कर 2,883 करोड़ रुपये हो गया। यह 6235 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

खेल एवं युवा मंत्रालय का बजट भी इसी तरह 767 करोड़ रुपये से बढ़कर 1620 करोड़ रुपये हो गया। मुंबई के आदर्श सोसायटी घपले में क्या केवल मुख्यमंत्री बदल दिए जाने से कांग्रेस नीत सरकार की कारगुजारियां ढक जाएंगी? आदर्श सोसायटी घोटाला वस्तुतः हमारे वीरों की शहादत का अपमान है। कथित तौर पर हमारे जवानों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने के लिए आदर्श सोसायटी को मुंबई के तटवर्ती संवेदनशील इलाके में रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराई गई थी।

बिल्डर लॉबी और राजनीतिक साठगांठ से इसमें आम नागरिकों के लिए भी फ्लैट आवंटन का प्रावधान बनाया गया। जांच में महाराष्ट्र कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के परिजनों के नाम फ्लैट होने का

खुलासा हुआ है। अशोक राव चव्हाण से त्यागपत्र भले ही ले लिया गया हो, किंतु उस घोटाले में विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे और नारायण राणे का नाम भी प्रमुखता से आ रहा है। इन नेताओं पर कांग्रेस का मौन क्यों?

इस सरकार के कार्यकाल में हुआ चीनी घोटाला आम आदमी के सरोकारों

मुंबई के आदर्श सोसायटी घपले में क्या केवल मुख्यमंत्री बदल दिए जाने से कांग्रेस नीत सरकार की कारगुजारियां ढक जाएंगी? आदर्श सोसायटी घोटाला वस्तुतः हमारे वीरों की शहादत का अपमान है। कथित तौर पर हमारे जवानों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने के लिए आदर्श सोसायटी को मुंबई के तटवर्ती संवेदनशील इलाके में रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराई गई थी।

के प्रति सरकार की संवेदनहीनता को ही साबित करता है। सरकार ने जानबूझकर ऐसी नीति बनाई जिससे जमाखोर व्यापारियों को कई गुना मुनाफा हुआ, जबकि बाजार में चीनी महंगी होती गई और किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिला।

पिछले साल गन्ने की सामान्य उपज होने के बावजूद सरकार ने 48,000 टन चीनी निर्यात करने का आदेश जारी किया था। यह निर्यात 12 रुपये प्रति किलो की दर से किया गया। इससे घरेलू बाजार में चीनी की किल्लत पैदा हो गई। छह महीने के अंदर ही सरकार ने चीनी आयात का फैसला किया और इस बार चीनी का आयात 27 रुपये प्रति किलो की दर से किया गया। इस सरकार ने राहत के नाम पर भेजी जाने वाली सहायता में भी घपलेबाजी करने से गुरेज नहीं किया।

पंजाब सरकार की आटा–दाल योजना को विफल करने के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त खाद्यान्न देने से मना कर दिया था। सरकार के पास पर्याप्त

स्टॉक नहीं होने का बहाना किया गया, जबकि केंद्र सरकार तब दो रुपये किलो की दर से चावल का निर्यात अफ्रीकी देशों को कर रही थी।

हकीकत यह है कि मानवीय आधार पर दी जाने वाली यह राहत पीड़ित देशों को न भेजकर अन्यत्र अधिक दरों पर बेची गई। इससे सरकार को करीब 2500 करोड़ रुपये का चूना लगा। लगता है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार के बीच चोली–दामन का साथ है।

अस्सी के दशक के बोफोर्स दलाली कांड के खुलासे के बाद से कांग्रेस नीत केंद्र व राज्य सरकारों पर घोटालों के कई आरोप सामने आते रहे हैं। बोफोर्स दलाली कांड, हर्षद मेहता का शेयर बाजार घोटाला, भरत शाह घोटाला, सुखराम के हिमाचल स्थित आवास से अरबों की बेनामी धनराशि का बरामद होना, राव सरकार में विश्वासमत के लिए सांसदों की घूसखोरी, अब्दुल करीम तेलगी का स्टांप घोटाला, इराक का तेल के बदले डॉलर

पिछले 60 वर्षों में भारत की अकूत संपत्ति भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों और करचोर व्यापारियों के द्वारा स्विस बैंकों में जमा की गई है। अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंसियल इंटेग्रिटी के ताजा अनुमान के अनुसार भारत से प्रतिवर्ष 1,35,000 करोड़ रुपये स्विस बैंक आदि में जमा कराया जाता है।

घोटाले में कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री नटवर सिंह के परिजनों का शामिल होना, अर्जुन सिंह के काल में शिक्षण संस्थानों के नाम पर की गई घपलेबाजी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष केतन देसाई द्वारा लंबे समय से अरबों की काली कमाई की सूची लंबी है।

यह स्थापित सत्य है कि पिछले 60 वर्षों में भारत की अकूत संपत्ति भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों और करचोर व्यापारियों के द्वारा स्विस बैंकों में जमा की गई है। अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंसियल इंटेग्रिटी के ताजा अनुमान के अनुसार भारत से प्रतिवर्ष 1,35,000 करोड़ रुपये स्विस बैंक आदि में जमा कराया जाता है।

प्रतिपक्ष और अन्य प्रबुद्ध संगठन लंबे समय से कालेधन की वापसी के लिए सरकार पर दबाव डालते आए हैं, किंतु सरकार की ओर से इस मामले में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

कटु सत्य तो यह है कि यहां चुप साधने के कारण ही बाकी सब मामलों में भी चुप्पी साधनी पड़ रही है। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

स्वदेशी चर्म उद्योग के वाहक, श्रीलेदर्स के प्रतिष्ठाता

सुरेश चन्द्र दे

के जन्म शतवार्षिकी पर

स्वदेशी पत्रिका परिवार को हार्दिक शुभकामना

सुरेश चन्द्र दे

जन्म शतवार्षिकी

(1911–2010)

जीन संवर्धित फसलें एवं पर्यावरण

आज यह शाश्वत सत्य है कि ये लालची कुछ विदेशी कंपनियां न तो किसानों का हित देखती, न ही उनके प्रति मानवीय संवेदनायें रखती हैं और उन्हें लूटने में लगी रहती हैं। परिणामस्वरूप कृषक अपनी हुई क्षति से कर्ज में चला जाता है, जिसका परिणाम किसान आत्महत्या के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है।

■ डा. सदाचारी सिंह तोमर

हमारे देश में भी जीन संवर्धित फसलों का प्रचलन बढ़ रहा है। आज बीटी कपास एवं बीटी बैंगन की खूब चर्चा हो रही है। इसके साथ ही लगभग 15 फसलें जो वैसीलस थुरंजेसिस (बीटी) जनित है प्रचलन हेतु तैयार की जा रही है। चूंकि यह फसल जीव (बैक्टेरिया) एवं पादप (बैंगन) जगत दोने के समिश्रण से बनी है अतः इसके प्रभाव का आंकलन आवश्यक हो जाता है। जिस तरह रासायनिक खादें, कीटनाशक दवायें आदि मृदा के साथ ही भूजल को प्रदूषित करते हैं वैसे ही जीन संवर्धित फसलों का मृदा, जल पर प्रभाव एवं इनके सेचन एवं परागकण का फैलाव तथा इनकी पत्तियां, तना, फलों का मानव तथा पशु स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन भी बहुत आवश्यक है।

आज यह विषय चर्चा में है कि जीव जगत एवं पादप जगत के मिश्रण से बनी ये फसलें क्या गुल खिलाती हैं यह विस्मयकारी है। ये फसलें 'स्वशेचन' एवं 'परशेचन' दोनों ही तरह की है अतः आसपास में उगने वाली इनकी मूल फसलें एवं वन्य फसलों पर भी ये प्रभावी हो सकती हैं। इनकी पत्तियां एवं तने जो पशुओं द्वारा खाये जाते हैं वे हानि कर सकते हैं। यथा बीटी बैंगन का प्रभाव है कि सूड़ी के पेट में आंतों में हानि पहुंचा देता है जिससे ये कीट स्वतः ही मर जाते हैं। इसी तरह ये सीधे खाने पर मनुष्य एवं पशुओं पर हानिकारक प्रभाव डालकर विनाश मचा सकते हैं।

कुछ समय पूर्व एक अध्ययन में यह पाया गया कि बीटी कपास की पत्तियां भेड़ बकरियों को हानि पहुंचा रही हैं। इसी तरह ये बी.टी. जनित या अन्य तरह से जीन संवर्धित फसल मृदा को भी प्रभावित कर सकती हैं। लम्बे समय तक इनका उपयोग करते रहने से ये मानव तथा पशु स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालती हैं इसका वृहद अध्ययन आवश्यक है।

जिस तरह नायट्रोजन वाली खादें से नाइट्रेट घुलकर पीने वाले जल को प्रदूषित करती है उसी तरह क्या जीव एवं पादप जगत मिश्रित ये फसलें कुछ प्रभाव तो नहीं बना लेंगी। वायु में उड़ते हुए परागकण कहां क्या गुल खिलायेंगे, इन सबका गहन अध्ययन बहुत आवश्यक है। भारतीय मानक संस्थान, अंतराष्ट्रीय मानक संस्थान, कृषि एवं खाद्य संगठन (एफ.ए.ओ.) विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि ने जीव संवर्धित फसलों के प्रचलन के पूर्व जो परीक्षण आवश्यक बताये हैं वही पूरी तरह कर लेने चाहिये तभी प्रचलन में लाने योग्य हैं। ऐसी भी आशंका है कि ऐसी फसलों को प्रचलित करने वाली कंपनियां ऐसी फसलों के ऐसे (टर्मिनेटर) बीज बनाएंगी जो आगे के बीज पैदा तो करें किंतु ये उगने योग्य ही नहीं रहें। जिससे मजबूर होकर किसान उन कंपनियों पर निर्भर रहेगा। साथ ही जो परंपरागत बीज है वे खत्म या लुप्त प्राय हो जाएंगे ऐसी आशंका है।

आज यह शाश्वत सत्य है कि ये लालची कुछ विदेशी कंपनियां न तो किसानों का हित देखती, न ही उनके प्रति मानवीय संवेदनायें रखती हैं और उन्हें लूटने में लगी रहती हैं। परिणामस्वरूप कृषक अपनी हुई क्षति से कर्ज में चला जाता है, जिसका परिणाम किसान आत्महत्या के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है।

अतः यह आवश्यक है कि इन जीन संवर्धित फसलों यथा बीटी कपास, बीटी बैंगन आदि के बीजों का रख–रखाव, वितरण, संवर्धन का अधिकार अपनी सरकार के पास हो तो जनता के प्रति उत्तरदायी हों। अन्यथा जिस तरह कीटनाशक कंपनी 'यूनियन कार्बाइड' ने भोपाल में गैस त्रासदी से विनाश मचाया था। उसी तरह कहीं ये कंपनियां हमारे मूल बीजों को खत्म करके एवं उनके बीजों पर हमें निर्भर बना दें, या ऐसे बीज बांटती रहे जो पड़ोस की उसी फसल या फसल तथा खरपतवार को भी प्रभावित करें एवं हमारा किसान पराश्रित रहे तथा कुछ न करने की मजबूरी में आत्महत्या करने पर बाध्य हो जाए।

यह सही है कि उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक है। इसीलिए वैज्ञानिक विधियों से उच्च उत्पादकता वाली किस्में, जीन संवर्धित फसलों आदि की वैज्ञानिक पद्धतियों, किस्मों को न लील जाए।

आज आवश्यकता है किसी जीन संवर्धित फसल को बाजार में उतारने के पूर्व उसके पूर्ण परीक्षण कर लिये जाए जिससे वह स्वास्थ्य के लिये किसी तरह की हानिकारक न साबित हो, उसके बीज का वितरण, संवर्धन रख–रखाव आदि पर हमारी सरकारों का नियंत्रण हो अन्यथा इस बौद्धिक संपदा अधिकार के युग में येनकेन प्रकारेण हम अपना अधिकार खो बैठेंगे।

अपने बीज जो शुष्क खेती, कम्पोस्ट खाद आदि देशी तकनीक से कम प्रवल से पैदा हो रहे थे अपने हाथ से चले जाने देंगे। दूसरे देशों की कंपनियों की ओर मुंह बायें उनके बीजों की याचना करेंगे और हमारे किसान पूरी तरह उन पर आश्रित हो जाएंगे। इस पर भी ध्यान रखना आवश्यक है।

सारांश यह है कि जीन संवर्धित फसलें कई तरह से भारतीय समाज (कृषकों) को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि इनमें नवीनता है अतः इस पर गहन अध्ययन एवं परीक्षणों की भी आवश्यकता है। केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों के साथ ही विश्व स्तर की प्रयोगशालाओं पर विशेष कर बीटी बैंगन के सीधे खाने तथा पकाकर खाने एवं दवा के रूप में कच्चे खाने पर कैंसरकारी कोई प्रभाव या अन्य हानिकारक प्रभाव का अध्ययन मानव एवं पशु पर उचित होगा।

आज इन प्रयोगशालाओं में अध्ययन की आवश्यकता है जो शासकीय क्षेत्रों में हों तथा पारदर्शी हो तथा ईमानदार लोगों द्वारा परीक्षण किया गया हों। मानव पर प्रयोगों के पूर्व बंदर, चूहे आदि पर पर्याप्त अध्ययन आवश्यक है जिससे उन पर क्या प्रभाव बना रहे इसका सत्यापन होगा।

अभी देश में भरपूर अध्ययन एवं विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन की कमी हैं इसके लिये जब तक पर्याप्त प्रयोगशालायें आए तब तक विश्वभर के उपलब्ध प्रयोगशालाओं के सहयोग की आवश्यकता है। हमें अपने बौद्धिक सम्पदा को सुरक्षित रखना है अतः विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए हमें फूंक–फूंक कर कदम बढ़ाने होंगे। यह देखना होगा कि विदेशी कंपनियां कृषकों के हित का कितना ध्यान रखती हैं। हमें जहां एक ओर नवीनतम तकनीक को आगे लाना है, वहीं मानव सभ्यता को हानिकारक प्रभाव से बचाना है एवं कृषकों को शोषण से भी बचाना है। ❑

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा में प्रधान वैज्ञानिक हैं।)

आंदोलन

अमरीकी नीतियों के विरोध में फूंका ओबामा का पुतला

बीते माह जमुई (बिहार) शहर के अटल बिहारी चौक पर स्वदेशी जागरण मंच के दर्जनों सदस्यों ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आगमन पर अपना विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया और ओबामा का पुतला फूंका।

इस मौके पर मंच के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य मुरारी झा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में जगह दिलाने के उद्देश्य से आए। उनकी यह यात्रा पूरी तरह से विदेशी निवेश पर आधारित है।

उन्होंने कहा कि विदेशी निवेश से भारत के छोटे एवं मध्यम व्यवसायी प्रभावित होंगे। जिसका मंच खुलकर विरोध करता है।

वही मंच के अनिल साह ने कहा कि विदेशी निवेश से छोटे–बड़े दुकानदार प्रतिस्पर्द्धा बाहर हो गए हैं और बड़ी कंपनियां अपना दबदबा की तैयारी कर रही है। ओबामा की यात्रा का एक मात्र उद्देश्य भारता में पांच वर्षों के अंदर पांच लाख अमेरिकी नागरिक को रोजगार देना है जिसका बुरा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके अलावा मंच के अनेक कार्यकर्ताओं ने अमरीकी नीतियों का विरोध किया।

विश्व बाजार की चुनौतियां

भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वर्तमान नौकरशाही (वास्तव में अफसरशाही) के ढांचे में वैश्वीकरण का लाभ वह नहीं उठा सकता है। माई बाप वाली अफसरशाही विकास में सबसे बड़ी बाधक है। हमारे अफसर हर योजना, हर कार्यक्रम पर कुंडली मारकर बैठे हैं। लेकिन किसी योजना या कार्यक्रम के क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन के बारे में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और न तो इस बारे में उनसे कोई सवाल किया जा सकता है। इसलिए आज जैसी स्थिति है उससे नहीं लगता है कि वर्तमान नौकरशाही के ढांचे के रहते भारत भूमंडलीकरण का पूरा लाभ उठा सकता है।

■ निरंकार सिंह

जब दुनिया के देशों के बीच दूरियां कम हो रही हों और बाजार खुला हो तो कोई भी देश वस्तुओं और सामानों के आवागमन को नहीं रोक सकता है। वैश्वीकरण हमारे जीवन के तमाम पहलुओं पर अपना प्रभाव डाल रहा है। कृषि, उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में भी वैश्वीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। पर हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक राष्ट्र के रूप में हम इन चुनौतियों का मुकाबला कैसे करे? क्या हमारी सरकार और नौकरशाही ने वैश्वीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए कोई रणनीतिक तैयारी की है? क्या वर्तमान नौकरशाही के ढांचे में भारत वैश्वीकरण का लाभ उठा सकता है?

वैश्वीकरण से पिछड़ेपन और गरीबी को कैसे कम किया जा सकता है। क्या विदेश व्यापार नीति के जरिए उत्पादकों को सीधे अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है? हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम नीति तो बना देते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर उसे लागू नहीं कर पाते हैं। ये सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब देश की सरकार और राजनेताओं को देना होगा।

जब दुनिया के देशों के बीच दूरियां कम हो रही हों और बाजार खुला हो तो कोई भी देश वस्तुओं और सामानों के आवागमन को नहीं रोक सकता है। वैश्वीकरण हमारे जीवन के तमाम पहलुओं पर अपना प्रभाव डाल रहा है। कृषि, उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में भी वैश्वीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। पर हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक राष्ट्र के रूप में हम इन चुनौतियों का मुकाबला कैसे करे?

भारत में वैश्वीकरण के संदर्भ में जमीनी सच्चाईयां और जरूरतें क्या हैं? इस पर एक गोष्ठी का आयोजन पिछले दिनों बंगलौर में किया गया। कट्स इंटरनेशनल द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में देश भर के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने–अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी थी। इस गोष्ठी में कट्स इंटरनेशनल के कार्यक्रम अधिकारी अनुतोष विश्वास ने बताया कि राजस्थान के 'कोटा डोरिया' के कारीगरों को जीआई रजिस्ट्रेशन का लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि उनकी

साड़ियां महंगी पड़ती हैं। लेकिन कुछ लोग कोटा डोरिया की नकली सस्ती साड़ियां बनाकर उसका लाभ उठा लेते हैं। कोटा डोरिया की नकली साड़ियों का दाम कम होने से देश में भी उनका व्यापार अधिक होता है।

लखनऊ की संस्था नीड के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि आठ साल पहले कपड़ों पर जरदोजी के काम पर पुरुषों का कब्जा था पर नीड के प्रयासों से आज जरदोजी का काम महिलाएं पुरुषों से अधिक कर रही है। अब केंद्रीय टैक्सटाइल सचिव रीता मेनन की सहायता से संस्था जरदोजी उत्पादक संघ बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ दिलाया जा सके।

गोष्ठी में चमड़ा, चाय, काफी, हल्दी, अनार उत्पादकों की समस्याओं पर भी विचार विमर्श हुआ। केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार के महानिदेशालय के संयुक्त सचिव अग्नेश्वर सेन ने कहा कि सरकार नीतियां बनाती है पर उनका लाभ लेने के लिए कामगारों को अपना संगठन बनाकर खुद पहल करनी होगी। इस काम में सामाजिक संगठन उनकी मदद कर सकते हैं। इन सब समस्याओं का सार यही था कि वैश्वीकरण की चुनौतियों का मुकाबला सरकार, सामाजिक संगठन और उद्यमी मिलकर कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कुशल रणनीति बनानी चाहिए।

उदारीकरण के बारे में विवाद का एक बड़ा विषय है कि उदारीकरण के नकारात्मक प्रभावों का प्रतिकार करने की सरकार की क्षमता। भारत जैसा देश मूलतः नौकरशाही के भरोसे चलता है। एक ऐसी नौकरशाही जिसमें अधिकांशतः स्वार्थपरक

नौकरशाह है। ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं लगता कि यह नौकरशाही भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की निरंतर बदलती हुई अर्थव्यवस्था के अनुरूप कोई आकार, बिना सरकार की भागीदारी के दे सकती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपने शासन करने की शैली को इस सीमा तक बदले कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच में कुछ ऐसी ऊर्जा व गति आए जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि बाजारी प्रक्रियाएं भ्रमित नहीं होगी और दोनों क्षेत्र मोटे रूप में अपने सामाजिक दायित्व का निरंतर निर्वहन करते रहेंगे।

नयी अर्थव्यवस्था में अब राजनेताओं और नौकरशाहों का काम अड़ंगा डालने के बजाए अपने उद्यमियों और उत्पादकों को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाने का हो गया है ताकि देश और प्रदेश खुले विश्व बाजार का लाभ उठा सके।

किसी भी प्रकार के आर्थिक सुधार लागू किए जाने पर, जिसमें व्यापारिक सुधार भी शामिल हैं, कुछ लोगों को उससे लाभ होगा तो कुछ को हानि। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि कोई ऐसा हल नहीं हो सकता जिसमें सुधारों से फायदा हो।

भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वर्तमान नौकरशाही (वास्तव में अफसरशाही) के ढांचे में वैश्वीकरण का लाभ वह नहीं उठा सकता है। माई बाप वाली अफसरशाही विकास में सबसे बड़ी बाधक है। हमारे अफसर हर योजना, हर कार्यक्रम पर कुंडली मारकर बैठे हैं। लेकिन किसी योजना या कार्यक्रम के क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन के बारे में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और न तो इस बारे में उनसे कोई सवाल किया जा सकता है। इसलिए आज जैसी स्थिति है उससे नहीं लगता है कि वर्तमान नौकरशाही के ढांचे के रहते भारत भूमंडलीकरण का पूरा लाभ उठा सकता है। भूमंडलीकरण का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत को प्रशासन के स्तर पर सुधार लाने होंगे। सरकारी संरक्षण कम करने और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में और अधिक भागीदारी निभाने के साथ–साथ सरकार

यदि उचित वातावरण व समुचित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी तभी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से लाभ अर्जित होंगे। जैसे कम कीमत पर और सही मात्रा में सही गुणात्मकता की बिजली उपलब्ध करानी पड़ेगी। कामगार बाजार को लचीला बनाना पड़ेगा ताकि बिना शोषण के उचित मूल्य पर समुचित व सही प्रकार के कामगार उपलब्ध हो सकें। नौकरशाही के तंत्र को कसना पड़ेगा, उसका नजरिया बदलना पड़ेगा एवं अनुशासित करना पड़ेगा। उनको यह सिखाना पड़ेगा कि वे लोक सेवक हैं और जनहित के प्रति उनका सीधा उत्तरदायित्व है। भ्रष्टाचार के इस वातावरण में भ्रष्ट अधिकारी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में बाधक सिद्ध होते हैं। अतः भ्रष्ट अधिकारियों से जागरूक रहने के लिए सरकार को प्रभावी प्रणाली निर्मित करनी पड़ेगी।

किसी भी प्रकार के आर्थिक सुधार लागू किए जाने पर, जिसमें व्यापारिक सुधार भी शामिल हैं, कुछ लोगों को उससे लाभ होगा तो कुछ को हानि। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि कोई ऐसा हल नहीं हो सकता जिसमें सुधारों से फायदा हो। उदारीकरण और विश्व व्यापार संगठन के समझौतों से उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि हम अपना सारा ध्यान प्रतिस्पर्धा के मंत्र पर केंद्रित करें। इस प्रतिस्पर्धा में ऐसे कुछ सुरक्षात्मक कदम हमें जरूर उठाने चाहिए ताकि उनसे इस प्रतिस्पर्धा में हमारा अस्तित्व भी कायम रह सके और राष्ट्र का विकास भी हो। इसके लिए लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की नीति अपनायी जाए। राष्ट्रीय लक्ष्य विशुद्ध लाभ का निर्धारित करें और क्षतिपूर्ति के कुछ ऐसे तरीके अपनाएं ताकि जिन लोगों को नुकसान हुआ हो, उन लोगों को क्षति की आवश्यक पूर्ति हो।

घरेलू आर्थिक सुधार एवं बहुपक्षीय एवं बहुचरणीय बातचीत उस सीमा तक जारी रखी जानी चाहिए जहां तक राष्ट्रीय शुद्ध लाभ के सकारात्मक होने की स्थिति हो। आर्थिक सुधारों के लिए अधिकांश जनता का समर्थन कायम रखने के लिए उन लोगों के क्षति की पूर्ति करने का हमें ध्यान रखना होगा जिन्हें उक्त सुधारों के कारण नुकसान हुआ है। इस क्षतिपूर्ति के लिए कुछ तरीके निकालने पड़ेगें जैसे पुनः प्रशिक्षण, शीघ्रता से दूसरे काम दिलवाने की सुनिश्चितता, नया व्यापार लगाने के लिए वित्तीय सहायता आदि।

हमारे उद्योगों को अपने ढांचे व कार्यप्रणाली में कई मूलभूत परिवर्तन करने होंगे। उद्योगों को संकटग्रस्त केवल प्रतिस्पर्धा ही नहीं करती, इसके लिए कई अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे कुप्रबंधन, नापाक इरादे, ऋण आदि का न मिलना।

वैश्वीकरण एक अवसर भी है जिसमें घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक एवं कार्यकुशलता हेतु आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत विदेशी कंपनियों एवं अन्य बड़े उद्योगों के सहयोग से उद्योगों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है और इस प्रकार उनकी उत्पादकता और लाभ में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

असंगठित कामागारों के लिए सरकार ऐसी पूरक नीतियां बनाएं, जिससे उनके उत्पादों में गुणात्मकता (क्वालिटी) आए, विशिष्ट कौशल एवं शिल्पकारी को प्रोत्साहन मिलें। ऐसी विशेषकर हस्तशिल्प के क्षेत्र में होना चाहिए, जहाँ भारतीय वस्तुएं सारी दुनिया में लोकप्रिय होना आरंभ हो गई है। ❑

कहा जाता है कि अच्छे से अच्छा यंत्र वह कहलाता है जो स्वयंचालित हो। समाज रूपी यंत्र भी तभी अच्छा माना जा सकता है जब वह स्वचालित हो। प्रत्येक स्थान की प्रारंभिक जरूरतों भोजन, वस्त्र, मकान आदि की व्यवस्था यदि लोग स्थानीय स्तर पर स्वयं कर सकते हों तथा दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुएं आवश्यकता होने पर बाहर से खरीद सकें, ऐसी व्यवस्था ही अच्छी से अच्छी व्यवस्था कही जा सकती है।

– आचार्य विनोबा भावे

नहीं लिया गया आतंकी हमले से सबक

अगर हमें 26/11 की पुनरावृत्ति से बचना है तो खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। क्या हम अपने शासन तंत्र में सुधार ला रहे हैं और अपनी राजसत्ता की कमियों को दूर करने की दिशा में काम कर रहे हैं? क्या हम बौद्धिक तबके को नई दिशा दे रहे हैं, जो लोगों में नया रुख और दृष्टिकोण पैदा करने में सहायक होगा? मैं भयभीत हूँ कि आज कोई भी ये सवाल नहीं पूछ रहा है, जबकि राष्ट्रीय पटल पर मुंबई हमले की स्मृतियां अभी धुंधलाई नहीं हैं।

■ जगमोहन

26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमला भारतीय गणतंत्र के इतिहास का सबसे घातक, सबसे त्रासद और सबसे अधिक सबक सिखाने वाला था। जान–माल के भारी नुकसान के अलावा इसने भारतीय राजसत्ता और शासनतंत्र में भारी दरार भी उजागर कीं। जो देश महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, वह विश्व के सामने एक ऐसे विशाल वृक्ष के समान नजर आया, जिसका तना खोखला है।

26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमला भारतीय गणतंत्र के इतिहास का सबसे घातक, सबसे त्रासद और सबसे अधिक सबक सिखाने वाला था। जान–माल के भारी नुकसान के अलावा इसने भारतीय राजसत्ता और शासनतंत्र में भारी दरार भी उजागर कीं। जो देश महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, वह विश्व के सामने एक ऐसे विशाल वृक्ष के समान नजर आया, जिसका तना खोखला है।

यह घटना भारत के बौद्धिक तबके के आंतरिक छिछलेपन को भी सतह पर लाई है। दस आतंकी पाकिस्तान के कराची से स्टीमर पर सवार होकर निकलते हैं, बड़े आराम से गेट ऑफ इंडिया के करीब मुंबई में दाखिल होते हैं और चार गुटों में बंटकर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की तरफ बढ़ जाते हैं। एक गुट ताज पर कब्जा कर लेता है, दूसरा लीओपोल्ड कैफे और ओबराय होटल पर धावा बोलता है, तीसरा छबद हाउस में घुस जाता है और चौथा छत्रपति रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। वे जहां भी जाते हैं, खून की नदियां बहा देते हैं। बड़ी बर्बरता और क्रूरता से निर्दोष लोगों का कत्लेआम करते हैं। तीन दिनों तक शहर पर आतंक का राज रहता है। जब तक उनमें से नौ मारे जाते हैं और एक जिंदा पकड़ लिया जाता है, वे 180 लोगों को मौत के घाट उतार चुके थे।

इस त्रासदी की कहानी बयान करने के लिए आंसू भी कम पड़ जाते हैं। इस अवसर पर अक्षमता का जो प्रदर्शन हुआ वह भी आतंकी घटना से कम त्रासद नहीं है। आतंकी हमला होने के बाद जिस तत्परता, सटीकता और संबद्धता की आवश्यकता थी, वह कहीं दिखाई नहीं दी। आतंकियों ने जिस खतरनाक रफ्तार और योजना से हमले को अंजाम दिया, उसके विपरीत राज्य व केंद्र सरकार का

सुरक्षा तंत्र बिल्कुल लचर और लाचार नजर आया। इसने खुद को संभालने में काफी वक्त लिया। सामाजिक ढांचे के अन्य घटकों ने भी खुद को किसी लायक साबित नहीं किया। उदाहरण के लिए, ताज होटल पर आतंकियों का सामना कर रहे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों को दिखाने की चैनलों में होड़ मची थी। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि इससे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका सुरक्षा बलों की पूरी कार्रवाई देखते हुए आतंकियों को नए निर्देश दे सकते हैं। यह सब तब हुआ जब भारत अनेक आतंकी हमलों का दंश झेल चुका था।

2008 में ही 13 मई को जयपुर में 8 बम विस्फोटों में 80 लोगों की मौत हो गई थी, 26 जुलाई को अहमदाबाद में श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों में 53 लोग मारे गए थे और दिल्ली में 8 धमाकों में 26 लोग मौत के मुंह में समा गए थे। दुर्भाग्य से, भारत ने न सुधरने की कसम खा रखी है, जिस कारण इस पर बार–बार हमले होते हैं। मुंबई हमले के बाद समाजशास्त्री और बुद्धिजीवी केंद्र व राज्य सरकार पर बुरी तरह बरस पड़े। इस घटना से उनकी सोच में भारी परिवर्तन आया था। वे आतंक की पीड़ा और भय से गुजरे थे। आतंकवाद के पहले चरण में कश्मीरी पंडित और अन्य निर्दोष लोगों को घाटी में मौत के घाट उतारा गया था। इस प्रबुद्ध वर्ग तब इन लोगों के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन नहीं किया था।

दूसरी तरफ, इन्हीं में से कुछ ने कश्मीरी युवाओं के अलगाव का सवाल उठाते हुए आतंकवाद को जायज ठहराने की कोशिश की। यहां तक कि आतंकियों को बख्शते हुए उन्होंने कश्मीर में राज्यपाल के शासन को कश्मीरी पंडितों की विदाई

का जिम्मेदार ठहराया। मीडिया से प्रगतिशील होने की प्रसिद्धि मिलने से इस प्रकार का रवैया इन लोगों का स्थायी भाव बन गया। इससे देश को बेहिसाब नुकसान उठाना पड़ा। जबकि घाटी में आतंकवादी निर्दोष लोगों का कत्लेआम कर रहे थे, जमीनी हकीकत से अनजान यह तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग आतंकवाद से लड़ने के लिए जरूरी सच्चाई, प्रतिष्ठा और इच्छाशक्ति का वध कर रहा था।

वे इस कटु सच्चाई को तभी देख पाए जब आतंकी पांच सितारा होटलों में भी लोगों का कत्लेआम करने लगे। 1980 के मध्य में जब भारतीय कूटनीतिज्ञ रवींद्र महात्रे की बर्मिंघम में जम्मू–कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने हत्या कर दी थी और जब भारत–वेस्टइंडीज क्रिकेट मैच के दौरान श्रीनगर में विध्वंसकारी नाटक हुआ था, तभी से मैं कश्मीरी लोगों में पंथिक उन्माद के माध्यम से आतंकवाद का जहर भरने के पाकिस्तानी षडयंत्र के बारे में आगाह कर रहा हूँ।

2008 में ही 13 मई को जयपुर में 8 बम विस्फोटों में 80 लोगों की मौत हो गई थी, 26 जुलाई को अहमदाबाद में श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों में 53 लोग मारे गए थे और दिल्ली में 8 धमाकों में 26 लोग मौत के मुंह में समा गए थे।

पाकिस्तान कश्मीरी उग्रवादियों को वही हथियार भेज रहा था, जो अमेरिका ने उसे अफगानिस्तान में रूस से लड़ने को दिए थे। किंतु किसी ने नहीं सुनी। दरअसल, मेरे जैसे जो लोगों को हाशिये पर धकेल दिया गया, जो आतंक के कैंसर की शुरुआत में ही ऑपरेशन कर इसे खत्म कर देना चाहते थे। अब आतंक की ये कोशिकाएं पूरे शरीर में फैल गई हैं और भारत के महत्वपूर्ण अंगों पर वार कर रही हैं। इनके खात्मे के लिए अब लंबा समय और भारी संसाधन चाहिए। पहले ही हजारों जानें और हजारों करोड़ रुपये इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। अमेरिकी नागरिक और लश्करे–तैयबा के एजेंट डेविड कोलमैन हेडली ने खुलासा किया कि

आतंकी हमलों का षड्यंत्र किस प्रकार रचा गया। किस प्रकार प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति तक के घरों का सर्वे किया गया और किस प्रकार तथाकथित गैर सरकारी अभिनेता और आईएसआई मिलकर भारत के खिलाफ खूनखराबा करने का षडयंत्र रच रहे हैं।

ब्रूस रिडेल के शब्दों में कहें तो पाकिस्तान विश्व का सबसे खतरनाक देश है, जो 21वीं सदी के तमाम दुरूस्वप्नों– आतंकवाद, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और परमाणु हथियार से लैस है। फरवरी 2008 के चुनाव के बाद भी सेना का देश पर और आईएसआई का सेना पर दबदबा कम नहीं हुआ। आईएसआई में अर्ध–स्वतंत्र तत्वों ने अपना प्रभामंडल बना लिया है। वहां का माहौल षडयंत्र और छलकपट से भरा है। पाकिस्तानी सत्ता भी अपनी दुष्टता और खलनायकी के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। पाकिस्तान में तालिबान के पूर्व राजदूत मुल्ला जईफ के अनुसार, पाकिस्तानी सत्ता के एक मुंह में दो जीभ हैं और एक सिर पर दो चेहरे हैं। इतने खतरनाक और कुटिल माहौल में क्या हम मुंबई हमले के दोहराव की आशंका से इनकार कर सकते हैं।

अगर हमें 26/11 की पुनरावृत्ति से बचना है तो खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। क्या हम अपने शासन तंत्र में सुधार ला रहे हैं और अपनी राजसत्ता की कमियों को दूर करने की दिशा में काम कर रहे हैं? क्या हम बौद्धिक तबके को नई दिशा दे रहे हैं, जो लोगों में नया रुख और दृष्टिकोण पैदा करने में सहायक होगा?

मैं भयभीत हूं कि आज कोई भी ये सवाल नहीं पूछ रहा है, जबकि राष्ट्रीय पटल पर मुंबई हमले की स्मृतियां अभी धुंधलाई नहीं हैं। ❑

सिंहभूम जिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन/तुलसी भवन

बिस्टुपुर, जमशेदपुर – ८३१००१

तुलसी भवन

तुलसी भवन संस्थान अपने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा अन्यान्य सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी के उन्नयन व विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान देने को और कृतसंकल्प है। कवि गोष्ठी, कहानी गोष्ठी, सांस्कृतिक गीत संध्या, नाटक मंचन तथा राष्ट्रभाषाभिमान कार्यक्रमों का आयोजन अपनी कार्य व्यवस्था का अंग है। तुलसी भवन की भूमिका केवल अपने कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं है। नगर में अनेक सांस्कृतिक, सांस्कृतिक संस्थाएँ विद्यमान हैं – जिन्हें अपने कार्यक्रमों के लिए मंच, विश्रामगृह या तुलसी भवन की अन्यान्य सुविधाओं की अपेक्षा रहती है। ऐसी संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पर सकारात्मक विचार कर तुलसी भवन सामंजस्य बिठाकर अपना कुछ प्रयास कर उपलब्ध कराने का है। पुस्तक संस्कृति तथा साहित्य के संवर्धन आयोजित करने वाली संस्थाओं की उन्नति चाहते हैं तथा विविध भाषा मंच सहित सम्मेलन, जमशेदपुर महानगर महिला शाखा, प्रबोधिनी ईश्वरीय ब्रह्मकुमारीज संस्थान, संस्कार भारती, सेवा भारती, खास विद्यालय परिसर, विद्यार्थी लाईट सिंगर, विद्यार्थ योग संस्थान, एन भारती, वेलफेयर, विकास, आत्मा आदि बहुत संस्थाओं को पूर्वोन्मुख एवं संघर्ष की सुविधा प्रदान की जाती रही है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य संस्कृतियों के बीच सेतु बनने के उद्देश्य लेकर चलने वाली संस्था सेतुबंध एवंम् द्वारा सौहार्द कवि का आयोजन, जमशेदपुर कौशल्या महिला परिषद् का स्वर्ण जयंती समारोह, साहित्यिक संस्थान 'सिंहभूमि' द्वारा – स्वतंत्रता सेनानी जनकवि यदु डोम पुरस्कार समारोह, विविध सांस्कृतिक परिषद् द्वारा विद्यालयी छात्रों का आयोजन तथा संस्कृत संस्थान द्वारा अन्तर्विद्यालय वार्षिक समारोह – उल्लेखनीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आते हैं। विद्यालयीन बच्चों हेतु एक नियमित 'पुस्तक रसास्वाद' कार्यक्रम का आयोजन भाषी रसास्वादनी की बुनियाद निर्माण की दृष्टि से अपने प्रकार का जमशेदपुर में अभिनव उपक्रम रहा है। विश्व प्रकाशन के संदर्भ पर जमशेदपुर में अखिल भारतीय पुस्तक सम्मेलन के आयोजन के अवसर पर आगामीय पुस्तिका उपलब्ध कराने तथा साहित्य के पोषितों हेतु आर्थिक सहयोग प्रेषित करना अपने कार्य – विस्तारक के परिचायक हैं। साहित्य, संस्कृति तथा सामाजिक जीवन में सक्रिय संस्थाओं को सहयोग अपनी कार्य व्यवस्था का अंग है। ऐसी उपलब्ध रिक्तियों कहीं नहीं पाया होने है तथा यह क्रम आगे भी अनवरत गतिमान रहेगा।

दृष्टि पथ

- हम जिस समाज में जीवन व्यतीत करते हैं, उसके उत्थान में अपना योगदान सुनिश्चित करना
- सांस्कृतिक पर्यावरण एवं पारम्परिक जीवन मूल्यों तथा संस्कारों का संरक्षण
- कार्य की पारदर्शी व्यवस्थाओं का निर्माण करना
- हिन्दी साहित्य के उन्नयन एवं विकास के उद्देश्य वाली को स्थापना के प्रयास निरंतर करना
- प्रत्येक साहित्यकार एवं साहित्यिक अभिरुचि का व्यक्ति, परिवेश के प्रति संवेदनशील रहते हुए अपने पूर्ण क्षमता, गतिशीलता व उत्साह के साथ सक्रिय सहयोग में प्रवृत्त हो सके, ऐसी संस्कृति एवं व्यवस्था का पोषण करना।

इस उद्देश्य सम्मेलन द्वारा समाज में उच्च मान्यों के साथ संस्थान की विशिष्टता अर्जित करने के प्रयास निरंतर हो सके – ऐसी कामना एवं विश्वास का आधार सम्मेलित करने की ओर कार्यकारिणी समिति का समूचा अधिकार एवं प्रयास यत्नशील बना हुआ है।

With

Best

Compliments

M/s K.K. Builders Pvt. Ltd.

TATA

TATA STEEL

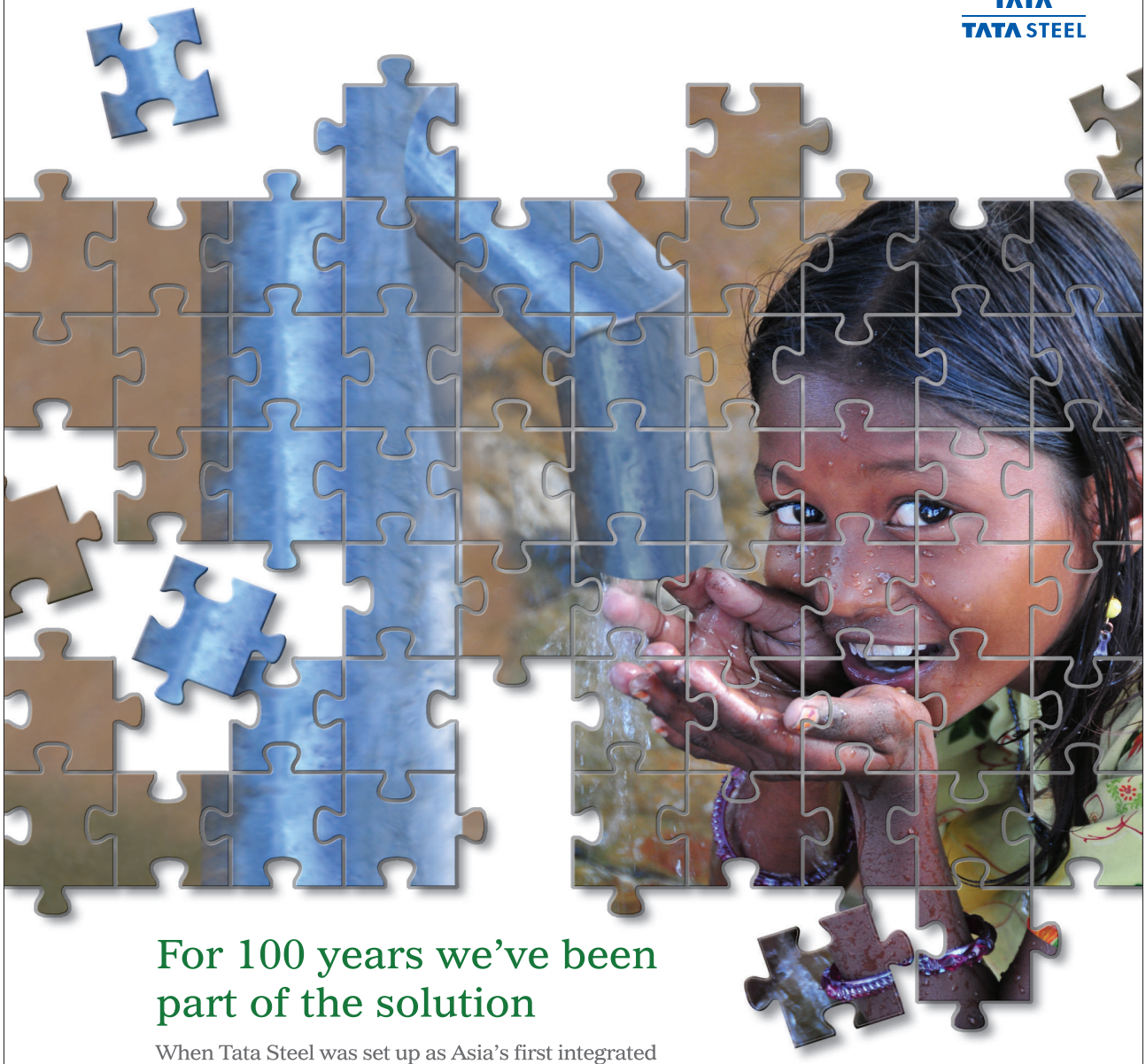

For 100 years we've been part of the solution

When Tata Steel was set up as Asia's first integrated steel plant in 1907, it was with a commitment to invest in the betterment of society. For 100 years now, the credo of service has been a guiding light inspiring us to find new ways to improve the quality of life. Through initiatives in education, health care, rural development & income generation, population management, environment management and tribal welfare, we are planting smiles everyday.

It's part of our vision to become the global steel benchmark in value creation and corporate citizenship.

TATA STEEL PRAGATI

Behtar Aaj Sunehra Kal

VERSUS '09

एक बार फिर विकास की ओर बिहार

राजग को सभी जातीय समूहों का मत मिला है। जिन 54 क्षेत्रों में मुस्लिम मत निर्धारक हैं उनमें ही 46 पर राजग की विजय का अर्थ साफ है। वास्तव में इस बदलाव के जो सकारात्मक पक्ष हैं उनको और ताकत देने की आवश्यकता है। इससे बिहार के साथ पूरे देश की राजनीति के लिए अच्छा संदेश जाएगा।

■ **अवधेश कुमार**

इस बात को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं कि बिहार विधानसभा चुनाव शत–प्रतिशत निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रहा है। जाहिर है नीतिश कुमार व राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समर्थन में जो एकपक्षीय चुनाव परिणाम आया है, उसे जन भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। चुनावी हिंसा न होना एवं मतदाताओं की लंबी कतारें वास्तव में प्रदेश की बदली सामूहिक चेतना को प्रतिबिंबित करने वाली थीं। महिलाओं की लंबी कतारें एक नई सामाजिक परिवर्तन की कहानी बता रही थीं। ऐसा लगता नहीं था कि उन्हें निर्देशित और नियंत्रित करने वाले कारक कहीं उपस्थित भी हैं। यह स्थिति पहले चरण से लेकर आखिर तक बनी रही। चौथा और छठा चरण, जिसमें माओवादी आतंक का खतरा सामने था, उसमें भी यही प्रवृत्ति जारी रही। बिहार के आम मतदाताओं की यह सामूहिक तस्वीर आने वाले परिणामों का आभास दे रही थी। पूरा प्रदेश उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम एक ही लहर में सराबोर था। एक्जिट पोल सर्वेक्षणों में केवल इस यथार्थ को ही अभिव्यक्ति मिली। चुनाव अभियान के दौरान साफ दिखा कि आम जनता की आवाज मुखर थी। एक

चुनावी हिंसा न होना एवं मतदाताओं की लंबी कतारें वास्तव में प्रदेश की बदली सामूहिक चेतना को प्रतिबिंबित करने वाली थीं। महिलाओं की लंबी कतारें एक नई सामाजिक परिवर्तन की कहानी बता रही थीं। ऐसा लगता नहीं था कि उन्हें निर्देशित और नियंत्रित करने वाले कारक कहीं उपस्थित भी हैं। यह स्थिति पहले चरण से लेकर आखिर तक बनी रही।

संप्रदाय को छोडकर सभी सामाजिक समूहों में लोग अपनी राजनीतिक इच्छा खुलेआम व्यक्त कर रहे थे। ज्यादातर लोग पूछने पर बता देते थे कि वे वोटिंग मशीन में किसके पक्ष में बटन दबाने वाले हैं, इसलिए इस बार चुनाव परिणामों का पूर्व आकलन आसान था। आकलन में समस्या तब आती है जब मतदाता अपना रुख बताने से कतराते हैं। कई कारणों से आम जागरूक मतदाता अपनी राजनीतिक

पसंद बताने से बचना चाहते हैं, लेकिन इस बार बिहार में बहुमत मतदाताओं के सामने ऐसी स्थितियां नहीं थीं। राजनीतिक समीकरणों में ज्यादातर मतदाताओं के सामने यह साफ था कि उन्हें समर्थन किसे देना है और लंबे समय बाद पहली बार कहीं किसी प्रकार की बदले की कार्रवाई का भय नहीं था। यह बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। यानी प्रदेश की राजनीति लंबे दौर के असामान्य माहौल से बाहर निकलकर सामान्य अवस्था में आ चुकी थी, जिसमें कोई भी लोकतंत्र के सहज माहौल में अपने राजनीतिक पक्ष को बता सकता था।

इस बदले माहौल का स्वाभाविक राजनीतिक प्रतिफल जो हो सकता है वही चुनाव परिणाम के रूप में हमारे सामने है। आखिर पिछले चुनाव की 46.27 प्रतिशत की जगह 52.43 प्रतिशत मतदान तथा 54.77 प्रतिशत महिलाओं का मतदान करना सामान्य घटना नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में केवल 44 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया था। इस बार मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या 10 प्रतिशत बढ़ी, जबकि पुरुषों की संख्या में केवल 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, छात्राओं को साइकिल एवं वजीफा के बाद महिलाओं की लंबी कतारें सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली थीं। नीतीश कुमार की कार्यशैली के कुछ पक्षों से असहमति व्यक्त की जा सकती है, किंतु उनके कार्यकाल में राजनीतिक माहौल भयमुक्त हुआ इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 2006 से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में कई गलत लोग भी फंसे हैं पर कुल मिलाकर करीब 52 हजार लोगों को सजा दिए जाने से राजनीतिक

अपराध एवं बाहुबलियों के प्रभाव से काफी हद निजता मिली। इससे चुनाव को भी हिंसामुक्त बनाने में मदद मिली और राजनीतक तनाव का भी अंत हुआ। चूंकि नीतीश के कार्यकाल में ऐसा हुआ इसलिए उसे ज्यादातर लोगों का समर्थन मिलना स्वाभाविक है। बिहार की सामूहिक राजनीतिक चेतना लालू बनाम नीतीश के संघर्ष से निर्मित हुई है। उनके सामने किसी आदर्श व्यक्तित्व के चयन का विकल्प नहीं था, बल्कि इन्हीं में से एक को चुनना था। नीतीश द्वारा विकास के नारे ने इसलिए मतदाताओं को प्रभावित किया, क्योंकि उनके सामने विकास का कोई आदर्श विकल्प नहीं था। लालू–राबड़ी के अविकास, नकारात्मक विकास और कुविकास के सामने पांच वर्ष की उपलब्धियां थीं। इसलिए जनता ने अग्रगामी प्रवाह का पक्ष लिया। इसमें धनपति और लालू काल के कई नेता भी राजग के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा पहुंच गए।

इस बार मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या 10 प्रतिशत बढ़ी, जबकि पुरुषों की संख्या में केवल 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, छात्राओं को साइकिल एवं वजीफा के बाद महिलाओं की लंबी कतारें सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली थीं। नीतीश कुमार की कार्यशैली के कुछ पक्षों से असहमति व्यक्त की जा सकती है, किंतु उनके कार्यकाल में राजनीतिक माहौल भयमुक्त हुआ इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।

दूसरी ओर राजद ही नहीं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अनेक ऐसा नेता जिन्हें जनाधार वाला माना जाता था बुरी तरह पराजित हो गए। स्वयं राबड़ी देवी की पराजय क्या साधारण घटना है? कांग्रेस के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष की पराजय का अर्थ क्या है? लालू–पासवान ही नहीं कांग्रेस तथा एक होकर चुनाव लड़ने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां तक इस बदली सामूहिक चेतना को अभिव्यक्त

करने में सफल नहीं रहीं। बदले माहौल के समर्थकों के लिए लालू–पासवान परखे हुए जोखिम थे और कांग्रेस भी। नीतीश सहित राजग के सारे नेताओं ने राजद–लोजपा के साथ कांग्रेस को भी निशाना बनाया और यह प्रश्न उठाया कि आखिर लंबे शासनकाल में इन्होंने प्रदेश को कहां छोड़ा? यह प्रश्न बदले हुए माहौल के अनुकूल था और इसका असर वही हुआ जैसा ये चाहते थे। इसमें लालू यादव की 334 एवं उनके पुत्र तेजस्वी की करीब 100 सभाएं भी काम नहीं आई।

चुनावशास्त्र की भाषा में कहा जा सकता है कि विपक्षी एकता का सत्तारूढ़ गठजोड़ के मुकाबले कमजोर होना इस विजय का मूल कारण है। जद–यू भाजपा के सामने अलग–अलग चार घटक थे और इनमें मतों का बंटना स्वाभाविक था। अगर इन सबका मत एक साथ मिला दें तब यह जद–यू भाजपा गठजोड़ से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। पर क्या कांग्रेस और वामदल एक साथ आने की मनःस्थिति में थे? क्या वामदलों में बिहार की मुख्य जनाधार वाली भाकपा (माले) किसी सूरत में लालू और कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल कर सकती थी। क्या अगले लोकसभा चुनाव में बहुमत का सपना पालने वाली कांग्रेस लालू–पासवान के गठजोड़ में जूनियर साझेदार बनती?

पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले 37 स्थानों पर चुनाव लड़कर 10 प्रतिशत मत पाए थे। वह इससे आगे बढ़ने की नीति पर चल रही है। दरअसल विपक्ष का एकजुट न होना वर्तमान राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक राजनीति की स्वाभाविक परिणति थी। सवाल यह भी है कि क्या इनकी एकता को जनता स्वीकार करती?

2005 के दोनों विधानसभा चुनाव

कहा जा सकता है कि शासन के सभी मोर्चे पर लालू–राबड़ी से बेहतर प्रदर्शन के कारण लोगों ने परिवर्तन को बनाए रखने के लिए मतदान किया।

बिहार के बहुमत का लालू–राबड़ी की नीतियों से विद्रोह का परिचायक था। रामविलास पासवान को मई 2005 के पहले चुनाव मे लालू विरोधी मत ही मिले थे। सरकार बनने देने में अड़ंगा डालने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा एवं अक्टूबर–नवंबर में उनके उम्मीदवार बुरी तरह पिट गए और जद–यू भाजपा गठजोड़ ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया।

कहा जा सकता है कि शासन के सभी मोर्चे पर लालू–राबड़ी से बेहतर प्रदर्शन के कारण लोगों ने परिवर्तन को बनाए रखने के लिए मतदान किया। इस तरह की चेतना कई प्रकार के विखंडित सामाजिक समीकरणों को भी आत्मसात कर लेती है। ऐसा ही बिहार में हुआ है। कुछ नीतीश की नीतियों से तो कुछ बदले माहौल से पूर्व में राजनैतिक ताकत के लिए बनाया गया चुनावी सामाजिक समीकरण चरमरा गया।

पिछले लोकसभा चुनाव में ही इसका संदेश मिल गया था, उसमें राजग को 175 विधानसभाओं में बढ़त मिली और इस बार तीन चौथाई से ज्यादा का बहुमत। भाजपा की सीटें जिस अनुपात में बढ़ीं उसकी कोई कल्पना नहीं रहा था।

इस परिणाम से साफ है कि राजग को सभी जातीय समूहों का मत मिला है। जिन 54 क्षेत्रों में मुस्लिम मत निर्धारक हैं उनमें ही 46 पर राजग की विजय का अर्थ साफ है। वास्तव में इस बदलाव के जो सकारात्मक पक्ष हैं उनको और ताकत देने की आवश्यकता है। इससे बिहार के साथ पूरे देश की राजनीति के लिए अच्छा संदेश जाएगा। मौजूदा चुनाव परिणाम के आधार पर कहा जा सकता है कि जब तक परिवर्तन का कोई बेहतर विकल्प नहीं आता या राजग गठजोड़ स्वयं कुछ नादानी नहीं करता, इसमें परिवर्तन की संभावना नहीं है। ❑

NARBOD CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
H.O.: 9, Tarapore Avenue, Harrington Road, Chetput, Chennai-600031
B.D. BODHANWALA
Managing Director
G-31, 'P' Road, Bistupur, Jamshedpur-831001
Phone: 2426564, 2431345, Fax: 0657-2423053, 2437128
E-mail: narbod@rediffmail.com

SAMAY CONSTRUCTION PVT. LTD.

106, Sakchi Highway, Near Bengali Club, Sakchi, Jamshedpur

SUPREME CONSTRUCTIONS

PROMOTERS & DEVELOPERS

R.Chandrashekhar
Authorised Signatory

Kunwar Singh Chowk (Ghora Chowk), Station Road,
Jugsalai, Jamshedpur-831006, Phone: 0657-3292585

राष्ट्रीय नदी गंगा को बचाने के उपाय

नदियों को शुद्ध–सदानीरा बनाने में गरीब–अमीर, हिन्दू–मुस्लिम, सिक्ख–ईसाई आदि सबकी साझी और समान भूमिका है। इसी तरह राज–समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन राज और राज्य संचालक वर्ग की जिम्मेदारी ज्यादा है। क्योंकि हमारी 'मां' नदियों को मैला ढोने वाली मालगाड़ी बनाकर मारने वाला काम सरकारों ने ही करवाया। इस गलत काम को रूकवाने हेतु प्रथम जिम्मेदारी भी भारत सरकार और राज्य सरकारों की ही बनती है।

■ राजेन्द्र सिंह

गंगा को बचाने के लिए अब देश भर के 11 राज्यों के लोगों ने ठान लिया है। प्रो. जी.डी. अग्रवाल का अनशन गंगा की अविरलता–निर्मलता का पाठ भारत सरकार को पढ़ाने वाला बना है। राजस्थान के समाज ने 27 वर्षों में सात नदियों अरवरी, रूपारेल, सरसा, भगाणी तिलदह, जहाजवाली, साबी और महेश्वरा को पुनर्जीवित करके यह दिखा दिया है कि गंगा का पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु सतही जल और भूजल का उपयोग अनुशाषित करना ही पड़ेगा।

गंगा लोकयात्रा का शुभारम्भ अरवरी नदी राजस्थान के गांव हमीरपुर से हुआ था। इस गांव में धरती का बुखार उतारने तथा मौसम का मिजाज ठीक करने का काम किया था। यही यात्रा एक नवम्बर, 2010 को प्रधानमंत्री आवास पर राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण की बैठक में जाकर सम्पन्न हुई। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में इस प्राधिकरण ने गंगा की अविरलता–निर्मलता सुनिश्चित करने वाली उन सब बातों को स्वीकार कर लिया। जिनके लिए यह गंगा लोकयात्रा आरम्भ हुई थी।

गोमुख से 135 किलोमीटर गंगा को नैसृगिक रूप में प्रवाहित करने का निर्णय सर्वसम्मत स्वीकार किया। लोहारी–नाग–पाला, भैरोघाटी, पालामनेरी परियोजनाओं को अंतिम मोहर लगाकर रद्द कर दिया। गंगा में अब नये बांध नहीं बनेंगे।

गंगा को बचाने के लिए अब देश भर के 11 राज्यों के लोगों ने ठान लिया है। प्रो. जी.डी. अग्रवाल का अनशन गंगा की अविरलता–निर्मलता का पाठ भारत सरकार को पढ़ाने वाला बना है। राजस्थान के समाज ने 27 वर्षों में सात नदियों अरवरी, रूपारेल, सरसा, भगाणी तिलदह, जहाजवाली, साबी और महेश्वरा को पुनर्जीवित करके यह दिखा दिया है कि गंगा का पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु सतही जल और भूजल का उपयोग अनुशाषित करना ही पड़ेगा। जिस तरह से अरवरी नदी की संसद ने अपनी नदी को जीवित रखने के लिए कम पानी में खेती करना शुरू किया है।

गंगा बेसिन की एक छोटी सी

अरवरी नदी को वहां के अनपढ़ समाज ने ही पुनः जीवित किया है। उजड़े सूखे कुओं को पुनः पानीदार और हरा–भरा बनाया। गांवों की लाचारी, बेकारी, बीमारी से विस्थापित ये अपने पसीने से पुनः पानीदार बने। शहरों से अब वापस पुनः अपने गांव में लौटने लगे हैं। अपनी पुनः जीवित नदी का गंगा संस्कार करके, नदी तीर्थ से अध्यात्म ज्ञान को जीवित करके, इन्होंने नदियों की पवित्रता और धरती की हरियाली बढ़ाई। शोशण–प्रदूषण, अतिक्रमण से नदी को आजादी प्रदान की है।

हमने अरवरी नदी के साथ जैसा किया है। वैसा ही सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार को अपनी गंगा की सभी नदियों के साथ करना चाहिए। गंगा नदी से कब्जे हटाने, प्रदूशण रोकने, जल शोषण बंद करने हेतु जिम्मेदार सरकार ही है।

हमारे देश के 11 राज्यों में गंगा की 210 छोटी व बड़ी नदियां हैं। इन सभी नदियों को जीवनदान देने के लिए सभी संबंधित सरकारें, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और राज्य सरकार जिम्मेदारी लें। ये ही समाज को साथ लेकर सभी नदियों को शुद्ध–सदानीरा बनायें। यह कार्य धन कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जिन्हें हमने अपने वोट से इस काम हेतु सरकारी प्रतिबद्धता व हक दिया है। वे अब इस कार्य को शीघ्रता से

करें। यदि ये नहीं करेंगे, तो समाज खड़ा होकर स्वयं करा लेगा।

गंगा लोकयात्रा में गंगा लोक ने ही मिलकर गंगा लोकादेश बनाया है। यह पूरी गंगा के लिए लोकादेश है। इस आदेश को भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को पूरा कराने में जुटना ही पड़ेगा। यदि सरकारों ने इस दिशा में काम शुरू नहीं किया, तो भविष्य में गंगा लोक सत्याग्रह जोर पकड़ेगा। सभी राज्य सरकारें मजबूर होकर इस काम को करेंगी। राज्य की जल–जमीन व जन–जीविका को स्वास्थ्य और समृद्ध बनाये रखने हेतु गंगा की सभी नदियों के लिए तत्काल सभी संबंधित सरकारें गंगा लोकादेश को पूरा करने में जुटें।

नदी के जल ग्रहण क्षेत्र से लेकर उद्गम–संगम तथा अंत तक मिट्टी का कटाव रोकने के लिए घास व वृक्षारोपण का कार्य करवाना चाहिए, जिससे नदियों का कटाव रूकेगा, जमाव रूकेगा। नदी तल को स्थायित्व मिलेगा।

कब्जे रोकने के लिए नदी के दोनों किनारों को सुरक्षित–संरक्षित घोशित करने हेतु तत्काल सीमांकन करना चाहिए। जिससे उसमें प्रदूषण, शोषण व अतिक्रमण रूके।

ग्राम पंचायत व नगर पालिकाओं को नदी किनारे मैला डालने का हक नहीं दिया जाये। ग्राम पंचायतों व नगरपालिकाओं ने नदियों को मैला ढोने वाले नालों में बदल दिया है। प्राकृतिक जल संशोधन, कोलकाता में 90 वर्षों से कारगर साबित हुआ है। अतः स्थानीय परिस्थितिकी और क्षमता को देखकर

TODAY SYNTHETICS LTD.
Yash Complex, Murli Vilas Road, Bhilwara
Phone: 01482-223090, 239649 (O) 253339, 232539
Fax: 01482-239649, E-Mail : todaybhl@datainfosys.net
सबसे अधिक बिकने वाला उत्तम भारतीय ब्रांड

स्थायी समाधान होना चाहिए। प्राकृतिक व सामुदायिक मलशोधन प्रक्रिया ही सफल है। उसे ही बढ़ाये। इसमें बिजली और मशीनों की जरूरत नहीं होती।

जलभराव क्षेत्र में सीमेंट–कंकरीट या अन्य निर्माण रोके और आगे के लिए रद्द करें। नदी भूमि का उपयोग न बदला जाये।

शुद्धता व पवित्रता बनाये रखने वाले घाट व मंदिरों जैसे धार्मिक स्थानों को ही स्वीकृति देनी चाहिए। नदी गंदी करने वाली सभी धार्मिक व अधार्मिक–आर्थिक विकास के नाम पर हो रही क्रियाओं को भी बंद किया जाए।

सर्वोपरि बाढ़ बिन्दु से दोनों किनारों पर कम से कम 500 मीटर क्षेत्र में पीपल, बरगद, कदम, गूलर व आंवला जैसे स्थानीय जैव विविधता का सम्मान करने वाली पंचवटी का रोपण व संरक्षण करना चाहिए। पेड़, जल शोधन के साथ–साथ किनारे का कटाव भी रोकेंगे।

नदियों की ऊपरी, मध्य व सबसे नीचे छोरों में जल उपलब्धता के अनुसार फसलों के चक्र सरकारों को निर्धारित करना चाहिए।

राज और समाज को मिलकर अरवरी नदी की तरह नदी घाटी संगठन बनाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। गंगा में भी सामुदायिक जिम्मेदारी और हकदारी देने हेतु राज्य सरकार पर गंगा लोक परिषद और राष्ट्रीय स्तर पर गंगा महापंचायत बननी चाहिए। यह संगठन प्रक्रिया गांव से राष्ट्र स्तर पर गठित कराने हेतु राज्य सरकार जिम्मेदारी लेंवे। गांवों में गंगा पंचायत, शहरों में गंगा पालिका, राज्य में गंगा लोक परिषद तथा राष्ट्रीय स्तर पर सबको मिलाकर गंगा महापंचायत बनें।

जैव विविधता के संरक्षण व सुरक्षा हेतु राज–समाज को मिलकर नियम बनाना चाहिए। गंगा अपना फिर वहीं गौरव पा सके, जिससे हर देशवासी गा सके ''मैं उस देश का वासी हूं। जिस देश में गंगा बहती है।'' जब गंगा की सरकार राष्ट्रीय नदी गंगा पर प्राधिकरण स्वयं गंगा अविरलता–निर्मलता कार्य हेतु आगे आकर जिम्मेदारी निभायेगा तभी भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी अंग भी अपनी गंगा हकदारी समाज को देकर समाज से ही जिम्मेदारी लेंगे।

जैव विविधता के संरक्षण व सुरक्षा हेतु राज–समाज को मिलकर नियम बनाना चाहिए। गंगा अपना फिर वहीं गौरव पा सके, जिससे हर देशवासी गा सके ''मैं उस देश का वासी हूँ। जिस देश में गंगा बहती है।''

मैं गंगा नदी सत्याग्रही हूं। मेरी नजर में गंगा की सभी 210 नदियों को बचाने में राज–समाज की साझी और अलग–अलग भूमिकायें हैं। इन्हें गंगा लोकयात्रा में मैंने विविध प्रकार से एहसास किया है। इन्हें पूरा कराने का आभास गंगा के लिए कार्य करने से ही होता है।

नदियों को शुद्ध–सदानीरा बनाने में गरीब–अमीर, हिन्दू–मुस्लिम, सिक्ख–ईसाई आदि सबकी साझी और समान भूमिका है। इसी तरह राज–समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन राज और राज्य संचालक वर्ग की जिम्मेदारी ज्यादा है। क्योंकि हमारी 'मां' नदियों को मैला ढोने वाली मालगाड़ी बनाकर मारने वाला काम सरकारों ने ही करवाया। इस गलत काम को रूकवाने हेतु प्रथम जिम्मेदारी भी भारत सरकार और राज्य सरकारों की ही बनती है। ❑

ADHUNIK ALLOYS & POWER LTD.
Adhunik (An Adhunik Group of Company)
2, Inner Circle Road, Shanti Hari Tower, Bistupur, Jamshedpur-831001
Phone : 0657-2224678/ 7224/ 7001/ 4622 Fax : 0657- 2227980
E-mail : adhunik_jsr@dataone.co.in
ANAND KUMAR
A.G.M. (Corporate Communication)
WORKS: Kandra Chowka Road, Kandra-832 402, Saraikella-Kharsawan (Jharkhand)
Phone: 06597-255409-421, Fax: 06597-255415, E-mail: aaplkandra@mailsify.com
Corporate Office: 2/1A, S.B. Road, 6th Floor, "Landsdowne Tower", Kolkata-700020.
Phone: 91-33-2289 0279-84/ 22428551, Fax : 91-33-2289 0285
Regd. Office: 14, N.S. Road, 2nd Floor, Kolkata-700001,
Phone: 91-33-2243 4355, 2242 8551, Fax : 91-33-2242 8553

प्राकृतिक संसाधनों को न्यायपूर्ण वितरण कीजिए

खनन कम्पनियों द्वारा नीति का खुलेआम उलंघन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को भूमि का मुआवजा बाजार भाव पर नहीं दिया जाता है। सामुदायिक भूमि एवं जंगल के अधिग्रहण से अनेक लोगों की जीविका प्रभावित होती है। इन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता है। स्थानीय लोगों की रोजगार में भागीदारी कम ही होती है। सरकार पुनर्वास नीति को लागू करने में असमर्थ है।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

देश के संविधान के प्रीएम्बल में कहा गया है कि देश की समस्त जनता ने इस गणतंत्र का गठन आर्थिक न्याय एवं अवसरों की समानता हासिल करने के लिये किया है। इस घोषणा का सीधा अर्थ हुआ कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर देश के समस्त नागरिकों का अधिकार होगा तथा इनका वितरण बराबरी के आधार पर किया जायेगा। जैसे भूमि में पड़ा कोयला एवं खनिज, नदियों में स्वच्छन्द बह रहा पानी, समुद्र से पकड़ी जाने पाली मछली, सूर्य की किरणें एवं हवा जिससे बिजली बनाई जाती है– इन सभी संसाधनों का उपयोग किसी विशेष वर्ग के लिये नहीं बल्कि जन सामान्य के लिये किया जायेगा। इस मन्तव्य को लागू करने के दो रास्ते हमारे सामने उपलब्ध हैं। एक रास्ता है कि संसाधनों का सीधे ही जनता में वितरण कर दिया जाये। जैसे कोयले एवं खनिज की रायल्टी को सीधे जनता में वितरित कर दिया जाये अथवा मछली पकड़ने के अधिकार को सीधे क्षेत्र के मछुआरों को बांट दिया जाये। दूसरा रास्ता है कि संसाधनों का अमीरों और उद्योगों द्वारा दोहन किया जाये। इसके बाद लाभ का एक हिस्सा जनता में वितरित किया जाये।

संसाधनों के वितरण के इन दो रास्तों में मौलिक अन्तर है। सीधे वितरण में जनता का हिस्सा सुरक्षित रहता है। जैसे समुद्र के एक क्षेत्र को स्थानीय लोगों द्वारा मछली पकड़ने के लिये आरक्षित कर दिया जाये और उस क्षेत्र में बड़े ट्रालरों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाये तो स्थानीय लोगों का हिस्सा सुनिश्चित हो जाता है। मछली का यह हिस्सा लोगों को मिलेगा या नहीं इसमें कोई संशय नहीं रह जाता है।

संसाधनों के वितरण के इन दो रास्तों में मौलिक अन्तर है। सीधे वितरण में जनता का हिस्सा सुरक्षित रहता है। जैसे समुद्र के एक क्षेत्र को स्थानीय लोगों द्वारा मछली पकड़ने के लिये आरक्षित कर दिया जाये और उस क्षेत्र में बड़े ट्रालरों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाये तो स्थानीय लोगों का हिस्सा सुनिश्चित हो जाता है। मछली का यह हिस्सा लोगों को मिलेगा या नहीं इसमें कोई संशय नहीं रह जाता है। इसके विपरीत ट्रालरों के प्राफिट से वितरण में संदेह बना रहता है। ट्रालरों को कितना प्राफिट हुआ, उस प्राफिट का वितरण कब और कितना किया जायेगा यह संदिग्ध बना रहता है। अतः संविधान के मन्तव्य को लागू करने का सीधा तरीका है प्राकृतिक संसाधनों में स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी

को सीधे निर्धारित कर दिया जाये।

दुर्भाग्य है कि उद्यमी प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी का विरोध तो कर ही रहे हैं – वे प्राफिट के वितरण में भी अड़ंगा लगा रहे हैं। उदाहरण खनन उद्योग का है। खनन मंत्रालय ने प्रस्ताव बनाया है कि कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ के 26 प्रतिशत हिस्से को स्थानीय लोगों को वितरित किया जाये। देश के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य खनिज सम्पदा से समृद्ध हैं किन्तु आर्थिक दृष्टि से गरीब हैं। खनिजों में समृद्ध अफ्रीका का भी यही हाल है। कारण यह कि खनन से होने वाले अधिकाधिक लाभ को कम्पनियों द्वारा शहरों को भेज दिया जाता है। स्थानीय लोगों को पुनर्वास एवं पर्यावरण की क्षति जैसे दुष्प्रभाव ही मिलते हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिये प्रस्तावित कानून का पुरजोर समर्थन किया जाना चाहिये। इन क्षेत्रों में नक्सलवादी गतिविधियां इसलिये बढ़ रही हैं कि स्थानीय लोग खनन के लाभ से वंचित हैं। लाभ के वितरण से इस समस्या का भी हल निकल सकता है।

सिद्धान्त है कि प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान किये गये खनिजों पर देश की सम्पूर्ण जनता का अधिकार होना चाहिये विशेषकर स्थानीय समुदाय का। जिस प्रकार खेत के नीचे बह रहे पानी पर भूमिधर का प्रथम अधिकार होता है उसी प्रकार खनिजों पर भी होना चाहिये। अथवा जिस प्रकार स्थानीय लोगों का नदी एवं समुद्र से मछली पकड़ने का अधिकार सुरक्षित रहता है उसी प्रकार अन्य संसाधनों के प्रति भी होना चाहिये।

इस प्रस्ताव का खनन कम्पनियों और व्यापार परिसंघों द्वारा विरोध किया जा रहा है। फेडरेशन आफ इंडियन

सिद्धांत है कि प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान किये गये खनिजों पर देश की सम्पूर्ण जनता का अधिकार होना चाहिये विशेषकर स्थानीय समुदाय का। जिस प्रकार खेत के नीचे बह रहे पानी पर भूमिधर का प्रथम अधिकार होता है उसी प्रकार खनिजों पर भी होना चाहिये। अथवा जिस प्रकार स्थानीय लोगों का नदी एवं समुद्र से मछली पकड़ने का अधिकार सुरक्षित रहता है उसी प्रकार अन्य संसाधनों के प्रति भी होना चाहिये।

मिनरल इंडस्ट्रीज ने सुझाव दिया है कि प्राफिट पर टैक्स आरोपित करने के स्थान पर खनिजों पर देय रायल्टी के अनुपात में स्थानीय समुदाय को धन उपलब्ध कराया जाये। ज्ञातव्य है कि रायल्टी खनिज की मात्रा पर निर्धारित होती है। खनिज के मूल्य पर उतार चढ़ाव से इस पर अंतर नहीं पड़ता है जबकि प्राफिट खनिज के मूल्यों से प्रभावित होता है। फेडरेशन का कहना है कि प्राफिट पर टैक्स लगाने से खनन में निवेष लाभप्रद नहीं रह जायेगा। इसी प्रकार का विरोध वैश्विक खनन कम्पनियों ने आस्ट्रेलिया द्वारा प्राफिट पर टैक्स लगाये जाने का किया था। परन्तु एक्सास्ट्रा नामक कम्पनी ने शीघ्र ही खनन के कार्य को पुनः शुरू कर दिया। इससे प्रमणित होता है कि निवेष प्रभावित होने की बात महज बंदर घुड़की है।

रायल्टी के अनुपात में रकम देना भी उचित नहीं है। समस्या है कि रायल्टी की दरें सरकार द्वारा बहुत ही न्यून स्तर पर निर्धारित की जाती है। उदाहरणतः लौह खनिज का वर्तमान मूल्य लगभग 5,000 रुपये प्रति टन है जबकि रायल्टी की दर मात्र 300 रुपये प्रति टन है। अतः रायल्टी के आधार पर स्थानीय भागीदारी निर्धारित करने में स्थानीय लोगों के हाथ केवल छाछ ही आयेगी–मलाई खनन कम्पनियों को ही मिलेगी। एक और समस्या है कि रायल्टी की दर कई वर्षों तक स्थिर रहती है जबकि विश्व बाजार में खनिज के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव आते हैं। आस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर

संविधान के प्रीएम्बल में व्यक्त की गयी भावना के अनुरूप प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार को मान्यता देनी चाहिये। प्राफिट में हिस्सेदारी के इस नियम को विकास की सभी योजनाओं पर लागू करना चाहिये। स्थानीय संसाधनों का देश हित के लिये उपयोग अवश्य होना चाहिये परन्तु स्थानीय लोगों के हित सर्वोपरी हैं। उन्हें प्राफिट में हिस्सा देने से स्थानीय विरोध नरम पड़ेगा और योजनाओं को लागू करना आसान हो जाएगा।

बताया है कि कुछ वर्ष पूर्व आस्ट्रेलिया को 3 डालर के खनिज निर्यात पर 1 डालर रायल्टी के रूप में मिलता था। समय क्रम में खनिजों को मूल्य बढ़ गये परन्तु रायल्टी दरें पूर्ववत् ही रहीं। फलस्वरूप आस्ट्रेलिया को मिलने वाली रकम घटकर 7 में 1 डालर रह गयी है।

देश के शीर्ष उद्योग समूह टाटा को रायल्टी के माध्यम से वितरण भी स्वीकार नहीं है। टाटा स्टील ने सुझाव दिया है कि स्थानीय लोगों को कमाने के अवसरों के माध्यम से राहत पहुंचानी चाहिये। उनकी धनोपार्जन की क्षमता का विस्तार करना चाहिये। धन वितरण करके लाभ पहुंचाना उचित नहीं है। इस तर्क में बल है जैसे कहावत है कि गरीब को मछली वितरित करने के स्थान पर मछली पकड़ना सिखाना चाहिये। समस्या है कि धनोपार्जन के अवसरों को चिन्हित करना और प्रभावितों को उन तक पहुंचाना दुष्कर है। सरकार ने पहले ही पुनर्वास नीति बना रखी है। खनन कम्पनियों द्वारा नीति का खुलेआम उलंघन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को भूमि का मुआवजा बाजार भाव पर नहीं दिया जाता है। सामुदायिक भूमि एवं जंगल के अधिग्रहण से अनेक लोगों की जीविका प्रभावित होती है। इन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता है। स्थानीय लोगों की रोजगार में भागीदारी कम ही होती है। सरकार पुनर्वास नीति को लागू करने में असमर्थ है। अतः प्रभावितों को लाभ कमाने के दूसरे अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे इसमें संदेह है।

निवेदन है कि संविधान के प्रीएम्बल में व्यक्त की गयी भावना के अनुरूप प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार को मान्यता देनी चाहिये। प्राफिट में हिस्सेदारी के इस नियम को विकास की सभी योजनाओं पर लागू करना चाहिये। स्थानीय संसाधनों का देश हित के लिये उपयोग अवश्य होना चाहिये परन्तु स्थानीय लोगों के हित सर्वोपरी हैं। उन्हें प्राफिट में हिस्सा देने से स्थानीय विरोध नरम पड़ेगा और योजनाओं को लागू करना आसान हो जायेगा। हाइवे, थर्मल, जल विद्युत परियोजनायें और स्पशल इकोनामिक जोन जोन इत्यादि सभी के प्राफिट में स्थानीय हिस्से को लागू करना चाहिये। ❑

Leading Name in Textile
Amar Industries Ltd Ishana Textiles
258-C, Focal Point, Phase-8, Ludhiana, Punjab
VIPAN JAIN 9316085009
VISHAL JAIN 9914127356

बर्बादी के बीजों को रोकिए

खनन कम्पनियों द्वारा नीति का खुलेआम उलंघन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को भूमि का मुआवजा बाजार भाव पर नहीं दिया जाता है। सामुदायिक भूमि एवं जंगल के अधिग्रहण से अनेक लोगों की जीविका प्रभावित होती है। इन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता है। स्थानीय लोगों की रोजगार में भागीदारी कम ही होती है। सरकार पुनर्वास नीति को लागू करने में असमर्थ है।

■ देविंदर शर्मा

पिछले कुछ सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और झारखंड के हजारों किसान संकट में फंस गए हैं। इन किसानों ने उड़द औरा तिल की फसल बोई थी, किंतु फसल में दाने नहीं आए। आर्थिक नुकसान को उठाने में असमर्थ कम से कम चार किसानों ने आत्महत्या कर ली। हजारों किसान आर्थिक संकट में फंस गए हैं। अनेक छोटे शहरों, गांवों और कस्बों में धरना–प्रदर्शन कर किसानों ने अपना रोष प्रकट किया है, किंतु इस अधिकारिक वायदे से अधिक कुछ हासिल नहीं कर पाए कि उन्हें उचित हर्जाना दिलाया जाएगा।

यह पहली बार नहीं हुआ कि तथाकथित उन्नत बीजों ने किसानों को गच्चा दे दिया था। न केवल राष्ट्रीय बीज निगम, बल्कि मोनसेंटो, पायोनियर हाई–ब्रीड और मायको जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीज भी अकसर बंजर निकल रहे हैं। या तो इनसे पौधा ही नहीं बनता या फिर दाना नहीं पनपता। फिर भी, सरकार द्वारा दोषी बीज कंपनियों को खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही किसानों को उनसे क्षतिपूर्ति दिलाई जा रही है। संसद के वर्तमान सत्र में पेश किए जानो वाला विवादित बीज बिल 2010 किसानों की लंबे समय से की जा रही मांगों की पूर्ति नहीं करता।

इस बिल का मूल मसौदा 2004 में तैयार किया गया था। खासे विचार–विमर्श के बाद पेश किए जाने वाले इस बिल में बीज कंपनियों के प्रति नरम रूख अपनाया गया है और किसानों के लिए राहत नहीं है। कृषि संसदीय समिति और अनेक नागरिक समूहों व किसान यूनियनों के महत्वपूर्ण सुझावों की अनदेखी करते हुए यह बिल बीज उद्योग के सुर में सुर मिला रहा है।

लगता है कि बीज बिल 2010 का मसौदा बीज उद्योग द्वारा तैयार किया गया है और इस उद्देश्य किसानों के बजाय बीज उद्योग को लाभ पहुंचाना है। प्रस्तावित संशोधन एक बार फिर से किसानों की कीमत पर निजी बीज कंपनियों के पक्ष में है। उदाहरण के लिए 26 अरब डॉलर की विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनी डूपोंट पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह अपनी प्रथामिकता बदल रही है और अब उसका ध्यान कृषि केमिकल के स्थान पर बीज की बेहतर नस्लें बेचने पर रहेगा। मोनसेंटो पहले ही बाजार में

लगता है कि बीज बिल 2010 का मसौदा बीज उद्योग द्वारा तैयार किया गया है और इस उद्देश्य किसानों के बजाय बीज उद्योग को लाभ पहुंचाना है। प्रस्तावित संशोधन एक बार फिर से किसानों की कीमत पर निजी बीज कंपनियों के पक्ष में है।

अपना सिक्का जमा चुकी है। अन्य बहुराष्ट्रीय बीज कंपनी स्विटजरलैंड की सिनगेंटा भी बीज बाजार में जड़ें जमा रही है। फिलहाल, पांच सौ से अधिक कंपनियां भारत में अपनी दुकान सजाने की तैयारी कर रही है।

जैसे–जैसे बीज उद्योग विकसित हो रहा है, निम्नस्तरीय और घटिया बीजों की फसल लहलहा रही है। खासतौर पर हाई–ब्रीड बीजों की बिक्री बड़ा फायदेमंद व्यापार बन गया है। बड़ी संख्या में कुकुरमुत्तों की तरह उभरने वाली बीज कंपनियां घटिया बीज बेचकर किसानों को मरने के लिए मजबूर कर रही है। कड़े नियंत्रणों के अभाव में, किसानों पर मुसीबत टूट रही है।

बीज बिल 2010 में बीजों की शुद्धता और उर्वरता को मानकों के अनुरूप न रखने पर अधिकतम एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। जाली बीज बेचने पर एक साल तक की जेल और अधिकतम पांच लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। खराब बीजों के कारण किसानों को होने वाले नुकसान का आकलन क्षेत्रीय विशेषज्ञ समिति के सहयोग से किया जाएगा, जिसके आधार पर किसानों को मुआवजा अदा किया जाएगा।

यह बिलकुल अनुचित है। जब बीज उर्वर नहीं होता और इससे दाना नहीं बनता तो किसान बर्बाद हो जाता है। यह किसानों के लिए विनाश से कम नहीं है। बहुत से किसान इसका नुकसान झेलने के बजाय मौत को गले लगाना पसंद करते हैं। इसलिए यह किसानों के लिए जीने–मरने का सवाल है। अच्छी फसल न केवल देश को खाद्यान्न सुरक्षा के लिए, बल्कि किसान की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी जरूरी है इसलिए इनके कारण किसानों को होने वाले नुकसान की पूर्ति महज बीजों के दामों से नहीं हो सकती। क्षतिपूर्ति में आजीविका का खर्च और न्यूनतम दायित्व राशि होनी चाहिए। इसलिए जरूरत नए बीज विधेयक की है।

परमाणु दायित्व विधेयक की तर्ज पर नए बीज दायित्व विधेयक में भी फसल बर्बाद होने की स्थिति में न्यूनतम आर्थिक क्षतिपूर्ति का प्रावधान होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी बीज कंपनी को वहन करनी चाहिए। कृषि मंत्री शरद पवार बीज उद्योग के प्रति नरम नहीं हो सकते क्योंकि यह महज उपभोक्ता उत्पाद नहीं है, बल्कि किसान परिवारों की आजीविका का साधन है। एक फसल की बर्बादी किसानों को कर्ज के मकड़जाल में फंसा सकती है।

जब बीज उर्वर नहीं होता और इससे दाना नहीं बनता तो किसान बर्बाद हो जाता है। यह किसानों के लिए विनाश से कम नहीं है। बहुत से किसान इसका नुकसान झेलने के बजाय मौत को गले लगाना पसंद करते हैं। इसलिए यह किसानों के लिए जीने–मरने का सवाल है।

नए बीज बिल में बीजों की कीमतों पर नियंत्रण होना चाहिए। किसानों को उचित दामों में बीज मिलने चाहिए। आजकल कंपनियां अपनी मर्जी से बीजों की कीमतें बढ़ा रही है। उदाहरण के लिए टमाटर का बीज 475 रुपये से 76000 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। चूंकि खराब बीजों पर जुर्माना बहुत कम है, इसलिए सरकार निम्नस्तरीय और घटिया बीजों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। जो कंपनियां ऐसे बीज बेच रही हैं, वे ब्लैकलिस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा फसल पूरी तरह बर्बाद होने की स्थिति में बीज कंपनी को फसल की पूरी कीमत जितना जुर्माना भरने का प्रावधान होना चाहिए। पुनर्पजीकरण के प्रावधान से बीज कंपनियों क एकाधिकार बढ़ता है। बीजों का पंजीकराण नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सीड्स में कराया जा सकता है। यह उचित होगा कि राज्य सरकारों को भी अधिकार दिया जाए कि उनके राज्य में पंजीकृत बीजों में से किनका इस्तेमाल होगा।

बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत पौधारोपण सामग्री और फूलों, सब्जियों व बागवनी बीजों के अनियंत्रित खुले आयात की अनुमति दे दी गई। इसके बाद गुणवत्ता जांच के बगैर ही खराब बीजों के खुले आयात की बाढ़ आ गई। इन बीजों के कारण देश में अनेक खतरनाक कीटों की आवक हो गई है। जिन पर नियंत्रण के लिए भारी मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। इसलिए तमाम बीज आयात पर गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच आवश्यक कर देनी चाहिए।

नए बिल में क्षतिपूर्ति और खराब बीजों से उपजी फसल के खेतों से निपटान के प्रावधाान की भी आवश्यकता है ताकि फसल बर्बाद होने पर बीजों का निर्यात करने वाली कंपनियों को जवाबदेय बनाया जा सके। भोपाल गैस त्रासदी के बाद यह और भी आवश्यक हो गया है, जहां यूनियन कार्बाइड कंपनी जहरीले कचरे की सफाई की जिम्मेदारी से बच निकली थी। ❑

With Best Compliments

HI-TECH CHEMICALS PVT. LTD.

(UNIT-1)

C-38 & 47, 4TH PHASE GAMHARIA

JAMSHEDPUR

शिक्षा संस्कार एवं संस्कृति का सुन्दर समन्वय स्थल

सस्वती विद्या मन्दिर

भूली नगर, पोस्ट ऑफिस : श्रमिक नगर, धनबाद – 828105

जिले का अग्रणी विद्यालय

:: विद्यालय की विशेषताएं ::

- भव्य एवं विशाल विद्यालय भवन।
- आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला।
- अत्याधुनिक कम्प्युटर कक्ष।
- एल.सी.डी. के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था।
- सुसज्जित बाँट निकल गार्डेन।
- विशाल क्रीडा स्थल।
- सभी प्रमुख मार्गों से विद्यालय बस की व्यवस्था।
- भारत कोकिंग लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त।
- बी.सी.सी.एल. कर्मियों के पाल्य के लिए केवल 50 प्रतिशत मासिक शिक्षण शुल्क।
- विगत दस वर्षों से शत–प्रतिशत परीक्षा परिणाम।

निवेदक : राजा राम शर्मा (प्राचार्य), विनय कुमार (सचिव), अनन्तनाथ सिंह (कोषाध्यक्ष)

सदस्यता संबंधी सूचना

मान्यवर,, आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्कः– हिन्दी – 100/– रुपए (वार्षिक), अंग्रेजी – 100 रुपए (वार्षिक)

आजीवन (हिन्दी) 1000/– रुपए, आजीवन (अंग्रेजी) – 1000/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

पता : **स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22**

परिसंवाद - महाशक्ति भारत : आगरा औद्योगिक संकुल का योगदान

आजादी से आज तक किसी भी सरकार ने औद्योगिक संकुलों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया - पी. मुरलीधर राव

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आगरा के औद्योगिक संकुलों के अध्ययन कराने के औचित्य को बताते हुए श्री राव ने कहा कि आगरा एक समृद्ध क्षेत्र है और यहां उद्योग एवं व्यापार की असीम संभावनायें हैं। उन्होंने यहां के उद्योगपतियों एवं व्यापारियों का आह्वान करते हुए कहा कि स्वदेशी जागरण मंच कभी भी विदेशों में व्यापार बढ़ाने या विदेशियों के साथ किसी समझौते का समझौता करने का विरोध नहीं करता. . .

आगरा उद्योग संकुल संकट में है और सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। यह कहना है स्वदेशी जागरण मंच के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक एवं वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मुरलीधर राव का।

महाशक्ति भारत आगरा औद्योगिक संकुल का योगदान विषय पर आयोजित परिचर्चा में पधारे मुरलीधरराव ने कहा कि आजादी से आज तक किसी भी सरकार ने औद्योगिक संकुलों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस परिचर्चा में आगरा के प्रमुख उद्योगपतियों के अलावा कई अर्थशास्त्रियों ने भाग लिया।

श्री मुरलीधर राव ने कहा कि औद्योगिक संकुल जिसको हम लोग इंडस्ट्रीयल क्लस्टर कहते हैं अपने बूते जिन्दा है। खास वर्ग के लोग ऐसे उद्योगों का संचालन करते हैं स्थानीय सामग्री लगाते हैं और स्थानीय स्तर पर ही पूंजी आदि की भी व्यवस्था करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के अधिकांश औद्योगिक संकुल एक कुटुम्ब की तरह काम करते हैं। सरकार की कोई सहायता इन्हें नहीं मिलती, इसके बावजूद ये उद्योग न सिर्फ अपनी पहचान बनाये रखते हैं बल्कि भारत के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि व्यवसाय और उद्योग हमारी परम्परा रही है और दुनिया में शायद भारत पहला ऐसा देश है जिसने पीढ़िया दर पीढ़िया एक ही तरह के व्यवसाय में संलग्न रहती हैं। उन्होंने कहा कि भारत की भूमिका विश्व स्तर पर बढ़ रही है। भारत धीरे–धीरे मजबूत हो रहा है और उनकी मजबूती में औद्योगिक संकुल सबसे अधिक योगदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच द्वारा अब तक 60 से अधिक अध्ययन कराये जा चुके हैं और इन अध्ययनों से यही परिणाम निकला है कि यदि औद्योगिक संकुल कुछ खास समस्याओं से निजात पा लेते हैं और सरकारी नीतियों में इनको महत्व मिलता है तो वह दिन दूर नहीं कि भारत सचमुच आर्थिक महाशक्ति बन जाये।

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आगरा के औद्योगिक संकुलों के अध्ययन कराने के औचित्य को बताते हुए श्री राव ने कहा कि आगरा एक समृद्ध क्षेत्र है और यहां उद्योग एवं व्यापार की असीम संभावनायें हैं उन्होंने यहां के उद्योगपतियों एवं व्यापारियों का आह्वान करते हुए कहा कि स्वदेशी जागरण मंच कभी भी विदेशों में व्यापार बढ़ाने या विदेशियों के साथ किसी समझौते का समझौता करने का विरोध नहीं करता।

उन्होंने कहा कि जब तक पूरे विश्व

JPL JANKI CORP LTD.
(Fabric Division)
Office: Mandapiya Chouraha, Chittor Road, Bhilwara - 311 001 (Raj.)
Phone: 01482- 249017, 249010, 249011, 249018, 329377, Fax: 249171
सर्वाधिक बिकने वाला उत्तम भारतीय ब्रांड

BLR
Bhilwara Ludhiana Road Lines
Shri Ajit Freight Carrier
Gill Roadways
Gill Logistics
Sugreev Bishnoi
98770-01957
93161-20502
Office 3748, St. No. 7, Shaheed Baba Deep Singh Nagar, LUDHIANA - 141 010 (PB.)
0161-2600057, 2601957
93164-19757
H.O. L-1, Transport Nagar, Azad Nagar, BHILWARA (M) 094145-75757

में भारत का व्यापार और लेन–देन नहीं बढ़ता तब तक भारत सुपरपावर नहीं बन सकता। उन्होंने इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा कि अभी 150–200 साल पहले तक भारत पूरे विश्व व्यापार का लगभग 21 फीसदी व्यापार भागीदारी करता था। काफी दिनों विश्व व्यापार में हमारी हिस्सदेारी 13 फीसदी तक रही। इधर के कुछ दशकों में हम 1 या 2 फीसदी पर आ गये हैं। बिना व्यापार बढ़ाये हम महाशक्ति नहीं बन सकते। उन्होंने भारत के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ओबामा भी आज यदि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलाने की कोशिश करते हुए दिखाये दे रहे हैं तो सिर्फ इसलिये कि उन्हें भारत से बहुत उम्मीदें हैं और भारत को उनसे सहयोग चाहिए।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मंच के अखिल भारतीय विचार मंडल प्रमुख डॉ. अश्विनी महाजन ने कहा कि एक तरफ मनमोहन सिंह की सरकार देश में विदेशियों को पूंजी लगाने के लिये तमाम सुविधाओं की घोषणा कर रहे हैं और दूसरी तरफ छोटे–छोटे उद्यमियों, खुदरा व्यापारियों व दुकानदारों से उनके रोजगार के अवसर छिन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार ने यह मंशा जतायी है कि खुदरा व्यापार के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को प्रवेश दिया जायेगा।

इसका मतलब यह है कि बड़े–बड़े ब्रांडों और बड़े–बड़े स्टोरों को बढ़ाने के लिये घरेलू खुदरा व्यापारियों को उनके रोजगार से वंचित कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहूलवालिया द्वारा अपनी पत्नी द्वारा संचालित शोध संस्थान के माध्यम से तैयार की गई रिपोर्ट के झूठे तथ्यों को आधार बनाकर सरकार के सामने यह दलील पेश की है कि खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी आने से किसानों को लाभ होगा।

इसके अलावा डॉ. महाजन ने कहा कि यदि सरकार को रोजगार के नये

सरकार देश में विदेशियों को पूंजी लगाने के लिये तमाम सुविधाओं की घोषणा कर रहे हैं और दूसरी तरफ छोटे–छोटे उद्यमियों, खुदरा व्यापारियों व दुकानदारों से उनके रोजगार के अवसर छिन रहे हैं।

अवसर सृजन करने का बूता नहीं है तो रोजगार छीनने का भी अधिकार नहीं है।

आगरा के पूर्व विधायक केशो मेहरा ने कहा कि छोटी–छोटी सरकारी गलतियों एवं खामियाजों के कारण आगरा के उद्योग एवं व्यापार को काफी नुकसान हुआ है उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच को बधाई दी कि मंच ने आगरा के औद्योगिक संकुलों पर अध्ययन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों का विकास होगा तो आगरा का भी विकास होगा और तभी भारत का विकास होगा।

इस कार्यक्रम में सह–आयोजक संगठन लघु उद्योग भारती एवं आगरा ब्रांच ऑफ इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस आफ इण्डिया के पदाधिकारियों ने भी आगरा के उद्योगों पर अध्ययन करने के मंच के फैसले की दिल खोलकर प्रशंसा की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूरन डाबर ने भी आगरा के उद्योग पर छाया संकट के बादलों को तुरंत दूर करने का सुझाव दिया। इस संगोष्ठी में कोल्ड स्टोरेज एवं फाउण्ड्री उद्योग के श्री राजेश गोयल, कोल्ड स्टोरेज एवं इंजीनियरिंग उद्योग के श्री राकेश गर्ग, पर्यटन उद्योग के श्री राजीव नरायन, होटल उद्योग के श्री राकेश चौहान, पर्यटन उद्योग के श्री रमेश बाधवा, हस्तशिल्प एवं मार्बल के श्री प्रहलाद अग्रवाल, पेठा उद्योग के श्री सुभाष गोयल, दरी गलीचा उद्योग के श्री बलवीर शरण गोयल, जूता दस्तकार कुटीर उद्योग के श्री भरत सिंह, जूता लघु उद्योग के श्री देवकीनंदन सोन, जूता दस्तकार कुटीर उद्योग के श्री देवी प्रसाद सरपंच, लघु उद्योग के श्री प्रमोद अग्रवाल और लघु उद्योग के श्री अमर मित्तल शामिल थे।

प्रस्तुति : (स्वदेशी जागरण मंच – लघु उद्योग भारती / आगरा ब्रान्च ऑफ इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस ऑफ इण्डिया)

संपादक को मातृ शोक

स्वदेशी पत्रिका के सम्पादक श्री विक्रम उपाध्याय की पूज्यनीय माताजी श्रीमती अहिल्या देवी जी का निधन दिनांक 06 दिसम्बर 2010 को हो गया। लगभग 70 वर्ष की आयु में इस जगत से नाता तोड़ने वाली श्रीमती अहिल्या देवी अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गयी हैं। वे अत्यन्त मृदुल स्वभाव की और हमेशा भगवान में लीन रहने वाली महिला थीं। वे पिछले कुछ वर्षों से लीवर की बीमारी से ग्रसित थीं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और मुक्ति एवं परिवार को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें।

श्री विक्रम उपाध्याय का संपर्क मो. 09760090083

समस्त स्वदेशी जागरण मंच परिवार

रपट

ओबामा की भारत यात्रा और खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश के विरोध में देश भर में प्रदर्शन

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा अमरीकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा के भारत आगमन पर देश भर में प्रचंड प्रदर्शन आयोजित किए गए। ये प्रदर्शन किसी देश के शासनाध्यक्ष के विरूद्ध नहीं बल्कि अमरीकी सरकार द्वारा भारत के खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए खोले जाने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों के विरोध में था। स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अमरीकी राष्ट्रपति के भारत आगमन से पहले वह अपनी खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति न दिए जाने की घोषणा करे। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के आगमन से पूर्व सरकार के विभिन्न मंत्रियों द्वारा लगातार यह बयान दिए गए कि सरकार जल्द ही इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति देने जा रही है। ऐसे में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा देश भर में प्रचंड विरोध प्रदर्शन किए गए और अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे और देश में खुदरा व्यापार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देने के प्रयासों के विरूद्व विरोध प्रदर्शित किया गया। ध्यातव्य है कि अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे से पहले अमरीकी खुदरा कंपनी वालमार्ट के प्रमुख माइकल डयूक कई सप्ताह तक भारत में डेरा डाले हुए थे। उनके द्वारा बहुराष्ट्रीय कपंनियों को खुदरा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दिए जाने के लिए देश भर में सरकार और व्यापार जगत में दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था।

दिल्ली में जंतर–मंतर पर लगभग सैकडों कार्यकर्त्ताओं ने ओबामा एवं सरकार की खुदरा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देने के विरूद्ध प्रदर्शन करते हुए बराक ओबामा का पुतला जलाया। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल, अखिल भारतीय विचार मण्डल प्रमुख डॉ. अश्वनी महाजन, क्षेत्रीय सहसंयोजक श्री दीपक शर्मा, दिल्ली प्रांत संयोजक श्री जितेन्द्र महाजन के साथ–साथ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री श्री विजय प्रकाश जैन, कॉन्फ्रेडेशन ऑफ एशोशियशन ऑफ ट्रेडर्स से श्री सतीश गर्ग, एफ.डी. आई. वाच से श्री धर्मेन्द्र राय ने धरना को संबोधित किया।

पंजाबः वालमार्ट ने सबसे पहले चोर दरवाजे से पंजाब में ही प्रवेश किया है। जालंधर और अमृतसर में भारतीय वालमार्ट के स्टोर खुले है। बराक ओबामा के पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें अमृतसर जाना था। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा वहीं अमरीकी राष्ट्रपति के विरोध की योजना बनी थी। लेकिन अंतिम क्षण कार्यक्रम में बदलाव होने से मुख्य विरोध प्रदर्शन दिल्ली में ही करने का फैसला किया गया। लेकिन पंजाब के कार्यकर्त्ताओं ने जालंधर, होशियारपुर एवं अमृतसर, तीन स्थानों पर विरोध के कार्यक्रम आयोजित किए और ओबामा का पुतला फूंका। क्षेत्रीय संयोजक श्री कृष्ण शर्मा, पंजाब संयोजक श्री सुभाष शर्मा तथा संघर्ष वाहिनी प्रमुख श्री आशु सांपला के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन आयोजित हुए।

केरलः 6 नवंबर को थिरूअनंतपुरम् एवं पालाघाट में विरोध का कार्यक्रम हुआ। खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश के बारे में तीन सम्मेलन भी आयोजित हुए। ये सम्मेलन पटनम्ठिथता, पालाघाट एवं कोल्लम में आयोजित हुए। अखिल भारतीय सहसंयोजक प्रो. कुमारस्वामी, क्षेत्रीय संगठक श्री बीजू, श्री गोपाल एवं श्री जनार्दन रेड्डी ने इस सम्मेलनों को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि केरल की व्यापारी एसोशिएशन के महामंत्री श्री एलेक्स की उपस्थिति इस अवसर पर रही। इस सम्मेलनों में केरल के विभिन्न व्यापारी एसोशिएशनों ने इन सम्मेलनों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया।

नागपुर एवं हिंगाघाटः नागपुर में भी विभिन्न व्यापारी एशोसिएशनों के समर्थनों से एक विरोध प्रदर्शन हुआ और सैकड़ों कार्यकर्त्ताओं ने नारेबाजी करते हुए बराक ओबामा और वालमार्ट के पुतलों का दहन किया। महाराष्ट्र प्रांत संयोजक श्री अजय पत्की, श्री बी.सी. भारतीय, हेयर सेलून संगठन के अध्यक्ष श्री मदन थुम एवं किराना व्यापारी एसोशिएशन के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश्वर रक्षक की भागीदारी प्रमुख रही। हिंगाघाट जैसे सुदूर इलाके में भी करंजा चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध यात्रा निकाली गयी। जिसका नेतृत्व जेठानन्द राजपूत, प्रदीप नागपुरकर और रमेश गंगाधर धारकर ने किया।

झारखंड़ एवं बिहारः झारखंड और बिहार में कुल मिलाकर 20 से भी अधिक स्थानों पर बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। प्रमुख विरोध प्रदर्शन जमशेदपुर, बोकारो, भागलपुर, जमोई इत्यादि स्थानों पर हुए। इस क्षेत्र से श्री सचेन्द्र वरियार, श्री वंदेशंकर, श्री कौशल किशोर, श्री दिलीप निराला, श्री मुरारी झा, अरविन्द त्रिपाठी सहित कई प्रमुख कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया।

उड़ीसाः उड़ीसा में बालनगीर, अंगुल, बालासौर एवं राउरकेला में विरोध मार्च निकाले गए। प्रदेश से श्री अन्नदा पाणी ग्राही, शुभ पटनायक और झारखंड और उड़ीसा के व्यापारी एशोसिएशन के ब्रजमोहन अग्रवाल की भूमिका प्रमुख रही।

मुरादाबादः डॉ. राजीव के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाली गयी और जिलाधिकारी को इस हेतु एक मेमोरेंडम भी दिया गया। ❑